Useful For Prelims

Date: 13 - 11 - 2025

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा

कुल 243 सीटों पर 66.91 फीसद मतदान, पुरुषों का आंकड़ा 62.8%, महिलाओं का 71.6%

जनसत्ता ब्यूरो

बिहार में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 66.91 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। विधानसभा का चुनाव दो चरणों में मंगलवार को संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी।

आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 243 सीटों पर 66.91 फीसद मतदान हुआ, जिसमें 62.8 फीसद पुरुषों ने जबकि 71.6 फीसद महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया । आंकड़ों में कहा गया है कि प्रदेश में मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही और पुरुषों की अपेक्षा करीब 8.8 फीसद अधिक महिलाओं ने इन चुनाव में मतदान किया। आयोग से प्राप्त अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में कुल 65.08 फीसद मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 69.04 और पुरुषों का फीसद 61.56 रहा। इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में मतदान फीसद बढ़कर 68.76 हो गया, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 74.03 और पुरुषों का फीसद 64.1 रहा। दोनों चरणों के कुल आंकड़े देखें तो महिलाओं का मतदान 71.6 फीसद रहा, जबकि पुरुषों का फीसद 62.8 रहा। राज्य के कुल 7,45,26,858 मतदाताओं में से 3,51,45,791 महिला और 3,93,79,366 पुरुष मतदाता थे। यह आंकड़ा सेवा मतदाताओं, ट्रांसजेंडर एवं पोस्टल बैलेट को शामिल किए बिना जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिकारिक अंतिम आंकड़े बाद में साझा किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे ने बताया, 'महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए उत्साहजनक है और यह राज्य की राजनीतिक राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। पांडे का मानना है कि नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया है।

विश्लेषण

पुरुषों की अपेक्षा करीब 8.8 फीसद अधिक महिलाओं ने चुनाव में मतदान किया।

पहले चरण में कुल 65.08 फीसद मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का फीसद 69.04 और पुरुषों का फीसद 61.56 रहा।

दूसरे चरण में मतदान फीसद बढ़कर 68.76 हो गया, जिसमें महिलाओं का फीसद 74.03 और पुरुषों का फीसद 64.1 रहा।

Jansatta Page No-16

दूसरी तिमाही में 7.2% की दर से बढ़ेगी आर्थिकी

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी के 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसमें निजी खपत वृद्धि प्रमुख चालक होगी। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि में पांच तिमाहियों में सबसे तेज गति से 7.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी, आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित होती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 28 नवंबर को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के जीडीपी वृद्धि अनुमानों पर आधिकारिक आंकड़े जारी करेगा। इंडिया रेटिंग्स के अर्थशास्त्री पारस जसराय ने कहा, 'उच्च तथा निम्न आय वाले परिवारों दोनों की स्थिर वास्तविक आय में बढ़ोतरी वृद्धि का प्रमुख चालक है। अनुकूल आधार-आधारित वस्तु निर्यात वृद्धि के साथ-साथ सर्विसेज जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा दिया।

Dainik Jagaran Page No-11

भारत में तपेदिक के मामलों में गिरावट, तेजी से घटा संक्रमण

नई दिल्ली, 12 नवंबर (ब्यूरो)।

देश में तपेदिक (टीबी) के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है। संक्रमण के मामले वैश्विक औसत से दोगुनी रफ्तार से घटे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 की तुलना में साल 2024 में टीबी संक्रमण की दर में 21 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 मामले थे, वहीं 2024 में यह घटकर 187 प्रति लाख रह गए।

यह गिरावट वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी है। मंत्रालय के अनुसार, एचआइवी-निगेटिव लोगों में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में भी वैश्विक औसत से अधिक कमी दर्ज की है। यह सुधार समय से पहचान, प्रभावी उपचार और सामुदायिक भागीदारी के कारण संभव हो पाई। देश में टीबी उपचार की पहुंच 92 फीसद तक हो गई है। यह वैश्विक 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' के औसत से आगे है।

साल 2024 में कुल 26.18 लाख टीबी मरीजों का निदान किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार सफलता दर 90 फीसद रही, जो कि वैश्विक सफलता दर 88 फीसद से अधिक है।

भारत में दवा-प्रतिरोधी टीबी की पहचान के लिए 'रिफैम्पिसिन' संवेदनशीलता परीक्षण कवरेज 92 फीसद तक पहुंच गया है, जबकि वैश्विक औसत 83 फीसद है। इससे रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर समय पर इलाज शुरू करने में मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2024 में शुरू हुए टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत देश में नई तकनीकों को अपनाया गया है।

Jansatta Page No-15

भारत में 2035 तक औसतन तीन प्रतिशत की दर से बढ़ेगी तेल की मांग : आइईए

नई दिल्ली, प्रेट्र: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) ने बुधवार को कहा कि भारत अगले दशक में तेल की मांग में वृद्धि का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत में ऊर्जा की मांग सबसे तेजी से बढ़ रही है और यह 2035 तक प्रत्येक वर्ष औसतन तीन प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। देश की ऊर्जा की बढ़ती मांग चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया की संयुक्त मांग से भी ज्यादा होगी, जो वैश्विक तेल बाजारों को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

आइईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वर्तमान नीति परिदृश्य में 2050 तक तेल प्रमुख ईंधन बना रहेगा। पिछले दस वर्षों में तेल की मांग में 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि चीन में हुई है, लेकिन यह तस्वीर अब बदल रही है और भारत तेल की मांग में वृद्धि का नया केंद्र बन रहा है। अगले दस वर्षों में वैश्विक तेल मांग वृद्धि में भारत अग्रणी रहेगा, और 2035 तक वैश्विक स्तर पर उत्पादित अतिरिक्त बैरल का लगभग आधा हिस्सा भारत की ओर जाएगा। कार स्वामित्व में तेजी से वृद्धि, प्लास्टिक, रसायन और विमानन की बढ़ती मांग के साथ खाना पकाने के लिए एलपीजी के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत का तेल उपयोग 2024 के 55 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2035 में 80 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा।

- चीन व दक्षिण-पूर्व एशिया की संयुक्त मांग से ज्यादा होगी भारत की जरूरत
- दस वर्षों में चीन में तेल की मांग में 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई

20 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ जाएगी तेल की मांग

भारत में तेल की मांग 2035 तक 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ जाएगी, जो किसी भी देश में होने वाली सबसे बड़ी वृद्धि है। 2035 तक अगली सबसे बड़ी वृद्धि अफ्रीका 12 लाख बैरल प्रतिदिन और दक्षिण-पूर्व एशिया में 10 लाख बैरल प्रतिदिन होगी। सीमित घरेलू उत्पादन के चलते इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता और बढ़ेगी। आइईए ने अनुमान लगाया है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में आयात पर निर्भरता 2024 के 87 प्रतिशत से बढ़कर 2035 में 92 प्रतिशत हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को छोड़कर सभी प्रमुख उत्पादक देशों में 2035 तक कोयला उत्पादन में गिरावट आएगी। भारत में कोयला उत्पादन 2035 तक लगभग पांच करोड़ टन के स्तर तक बढ़ जाएगा।

Dainik Jagaran Page No-11

जीएसटी में कटौती के कारण

खुदरा महंगाई दर घटकर अब तक के निचले स्तर पर

नई दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा)।

खुदरा महंगाई दर अक्तूबर में घटकर रेकार्ड निचले स्तर 0.25 फीसद पर आ गई। सब्जी, फल, अंडा जैसे खाने के सामान के सस्ता होने के साथ आम लोगों के उपयोग वाली लगभग 380 वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती से महंगाई दर में नरमी आई है।

अक्तूबर माह की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित महंगाई दर वर्तमान शृंखला (आधार वर्ष 2012) में सबसे कम है। इसमें जनवरी, 2014 से आंकड़े शामिल हैं। खुदरा महंगाई दर सितंबर में 1.44 फीसद और बीते साल अक्तूबर में 6.21 फीसद थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर में खाद्य महंगाई दर में गिरावट आई और यह शून्य से नीचे 5.02 फीसद रही।

एनएसओ ने कहा कि अक्तूबर, 2025 के दौरान कुल (हेडलाइन) महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर में गिरावट मुख्य रूप से जीएसटी दर में कटौती, अनुकूल तुलनात्मक आधार प्रभाव एवं तेल व वसा, सब्जियों, फलों, अंडे, जूते, अनाज, परिवहन तथा संचार की महंगाई दर में नरमी के कारण आई है। रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई दर दो फीसद घट-बढ़ के साथ चार फीसद पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य रूप से खुदरा महंगाई दर पर गौर करता है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हुई हैं। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर घटी है और यह क्रमशः 0.25 फीसद और 0.88 फीसद रही।

सबसे अधिक महंगाई दर केरल (8.56 फीसद) में रही, उसके बाद जम्मू-कश्मीर (2.95 फीसद), कर्नाटक (2.34 फीसद), पंजाब (1.81 फीसद) और तमिलनाडु (1.29 फीसद) का स्थान रहा। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महंगाई दर में कमी आई है। महंगाई दर के बारे में इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खाद्य कीमतों में नरमी के साथ खपत वाली कई वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाए जाने से महंगाई में कमी आई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अनुमान को 2.6 फीसद से और कम कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अक्तूबर, 2025 के नीति दस्तावेज के नरम रुख के साथ, दिसंबर, 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में 0.25 फीसद की कटौती का समर्थन करेगी। यह स्थिति तबतक बनी रहेगी जब तक कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से ऊंची न रहे। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा कि सितंबर के अंत में जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाये जाने के साथ इसका सकारात्मक प्रभाव अक्तूबर की महंगाई दर दर में कमी के रूप में दिखा है। सिन्हा ने कहा कि मौद्रिक नीति के नजरिये से, महंगाई दर में नरमी आरबीआई को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देने के लिए ज्यादा गुंजाइश देती है। हालांकि, बाहरी चुनौतियां और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक तीन से पांच दिसंबर को होगी। एनएसओ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े 1,181 गांवों और 1,114 शहरी बाजारों से एकत्रित करता है।

सबसे अधिक महंगाई दर केरल (8.56%) में रही, उसके बाद जम्मू-कश्मीर (2.95 फीसद), कर्नाटक (2.34 फीसद), पंजाब (1.81 फीसद) और तमिलनाडु (1.29 फीसद) का स्थान रहा। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महंगाई दर में कमी आई है।

अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खाद्य कीमतों में नरमी के साथ खपत वाली कई वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाए जाने से महंगाई में कमी आई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अनुमान को 2.6 फीसद से और कम कर सकती है। यह स्थिति अक्तूबर, 2025 के नीति दस्तावेज के नरम रुख के साथ, दिसंबर, 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में 0.25 फीसद की कटौती का समर्थन करेगी।

चिंताजनक

विशेषज्ञों की राय

विस्फोटकों में उर्वरक से लेकर रोजमर्रा के तत्त्वों का होता है इस्तेमाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 नवंबर।

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में घटना को 'बम विस्फोट' करार दिया गया है, जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञ यह जानने में लगे हैं कि क्या फरीदाबाद से मिली सामग्री का रासायनिक संयोजन लाल किले के पास हुए विस्फोट के अवशेषों से मेल खाता है।
जैन ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के साथ मिलाने पर एक अत्यंत अस्थिर और संवेदनशील मिश्रण बनता है।'

लाल किले के पास सोमवार शाम 12 लोगों की जान लेने वाले विस्फोट की जांच ने फरीदाबाद से बरामद 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

विशेषज्ञों की मानें तो विस्फोटकों का यह भंडार आक्सीडाइजर, ईंधन और सेंसिटाइजर के मिश्रण से बना अत्यंत अस्थिर संयोजन हो सकता है, जो अधिकांश औद्योगिक विस्फोटकों के रासायनिक सिद्धांतों के अनुरूप है। पुलिस को शक है कि फरीदाबाद में बरामद पदार्थों में अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल थे, और इस मामले में वे गैरकानूनी (अवैध गतिविधियां) रोकथाम कानून के तहत आतंकवाद-संबंधी धाराएं भी लागू कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में घटना को 'बम विस्फोट' करार दिया गया है, जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञ यह जानने में लगे हैं कि क्या फरीदाबाद से मिली सामग्री का रासायनिक संयोजन लाल किले के पास हुए विस्फोट के अवशेषों से मेल खाता है।

दिल्ली टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी के एप्लायड केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर मनीष जैन ने एजंसी को बताया, 'सभी विस्फोटक यौगिकों को मोटे तौर पर तीन घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है- ईंधन, आक्सीडाइजर और सेंसिटाइजर। उन्होंने कहा, 'अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट आक्सीडाइजर के रूप में काम करते हैं, जो दहन के लिए आक्सीजन प्रदान करते हैं, जबकि सल्फर और कार्बन जैसे तत्व ईंधन का काम करते हैं। जब सेंसिटाइजर जोड़ा जाता है तो मिश्रण के लिए काम आरंभ करना आसान हो जाता है और तेजी से जलने से लेकर विस्फोटक प्रतिक्रिया तक बढ़ सकता है।' अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों में और नियंत्रित औद्योगिक विस्फोटकों जैसे-अमोनियम नाइट्रेट-ईंधन में प्रयुक्त सबसे सामान्य आक्सीडाइजर में से एक है। लेकिन गलत तरीके से मिलाने पर या अतिरिक्त ईंधन के साथ मिलने पर यह अत्यंत अस्थिर हो सकता है।

जैन ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के साथ मिलाने पर एक अत्यंत अस्थिर और संवेदनशील मिश्रण बनता है।' दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कालेज में रसायन विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने विस्फोटकों की बरामदगी को गंभीर चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट एक शक्तिशाली आक्सीडाइजर है, पोटाशियम नाइट्रेट जलने के लिए आक्सीजन देता है, और सल्फर प्रज्वलन तापमान को कम कर प्रतिक्रिया के फैलने में मदद करता है। साथ मिलकर ये किसी मिश्रण की संवेदनशीलता और विनाशक क्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि बरामद सामान में से लगभग 360 किलोग्राम पदार्थ ज्वलनशील था।

भारत का भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति समर्थन

द्विपक्षीय साझेदारी को गति देने पर केंद्रित रही

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 नवंबर।

भारत ने बुधवार को भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति अपने 'अटूट' समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के साथ वार्ता की और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के तहत आयोजित कालचक्र दीक्षा समारोह में भूटानी नेतृत्व के साथ शामिल हुए।

बैठक के बाद मोदी ने भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करने में सिंग्ये के योगदान की सराहना की और कहा कि चर्चा ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित रही। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और कनेक्टिविटी में सहयोग पर चर्चा हुई। गेलेफू

माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में प्रगति की सराहना की, जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है।

सुबह मोदी ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में 'कालचक्र व्हील आफ टाइम एम्पावरमेंट' का उद्घाटन किया, जिसमें भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और सिंग्ये सहित शीर्ष भूटानी नेतृत्व ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसका बौद्ध समुदाय के लिए विश्वभर में अत्यंत सांस्कृतिक महत्त्व है। 'कालचक्र एम्पावरमेंट' वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव का हिस्सा है, जो भूटान में बौद्ध श्रद्धालुओं और विद्वानों को एक साथ लाया है।' नई दिल्ली रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में उनकी यात्रा के परिणाम हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को गति प्रदान करेंगे।

भूटान नरेश प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर विदा करने आए। मोदी की दो दिवसीय भूटान यात्रा समाप्त होने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सहित भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-2029) के प्रति भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि की।

मुलाकात कनाडा में जी7 की बैठक में एस जयशंकर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ।

कनाडा की विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 नवंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नियाग्रा में जी-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की आशा जताई।

जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए आनंद को बधाई दी और 'नए रोडमैप 2025' के कार्यान्वयन में प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा, 'हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होने की आशा करते हैं।' आनंद ने 'एक्स' पर कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, 'जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को मजबूत करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'

कनाडा ने जी-7 बैठक के लिए जिन साझेदार देशों को आमंत्रित किया है, उनमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन शामिल हैं। कनाडा ने पिछले सप्ताह कहा था कि जी-7 सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और समृद्धि, आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी।

Jansatta Page No-14

Hindustan Page No-15

काप30 : भारत में तीन दशक में 80,000 लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 नवंबर।

'जर्मनवाच' की रपट में कहा गया है कि जलवायु आपदाओं ने 1995 से 2024 तक 1.3 अरब लोगों को प्रभावित किया और लगभग 170 अरब अमेरिकी डालर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

रपट में चेतावनी दी गई है कि भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए ऐसी आपदाएं 'नई सामान्य' स्थिति बनती जा रही हैं, जिसके लिए तत्काल और अच्छी तरह से वित्त पोषित अनुकूलन उपायों की आवश्यकता है।

तीन दशक में जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत नौवें स्थान पर है, जहां लगभग 430 ऐसी घटनाओं में 80,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

ब्राजील के बेलेम में आयोजित काप30 सम्मेलन में पर्यावरण क्षेत्र के थिंक टैंक 'जर्मनवाच' की ओर से जारी 'जलवायु जोखिम सूचकांक (सीआरआइ) 2026' में यह दावा किया गया है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं के एक समूह की सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने मुख्य कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश की लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अधिकारियों ने बताया कि दो सुरक्षाकर्मियों को मामूली चोटें आईं। 'जर्मनवाच' की रपट में कहा गया है कि जलवायु आपदाओं ने 1995 से 2024 तक 1.3 अरब लोगों को प्रभावित किया और लगभग 170 अरब अमेरिकी डालर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। रपट में कहा गया है कि देश को मुख्य रूप से बार-बार आने वाली बाढ़, चक्रवात, सूखे और लू के कारण नुकसान हुए हैं, जो 'ग्लोबल वार्मिंग' के साथ और भी तीव्र हो गए हैं। 1998 में गुजरात में आए चक्रवात, 1999 में ओड़ीशा के 'सुपर साइक्लोन', 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और हाल में लू जैसी कई घटनाओं ने इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग को बढ़ाया है। भारत की स्थिति छिटपुट आपदाओं के बजाय एक 'निरंतर खतरे' का संकेत देती है, क्योंकि बार-बार होने वाली मौसमी घटनाओं ने विकास के लाभों को लगातार कमजोर किया है और आजीविका को नुकसान पहुंचाया है। भारत की विशाल जनसंख्या और मानसून की परिवर्तनशीलता के प्रति उच्च जोखिम इसे विशेष रूप से संवेदनशील बनाते हैं। रपट में कहा गया है कि अकेले 2024 में, भारत भारी मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ से इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ था कि उससे 80 लाख से अधिक लोगों पर असर पड़ा था और खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में इस तरह के हालात बने थे।

'जर्मनवाच' ने कहा कि वैश्विक स्तर पर 1995 और 2024 के बीच 9,700 से अधिक मौसमी आपदाओं ने 8.3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, लगभग 5.7 अरब लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,500 अरब अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तीन दशक में इस तरह की आपदाओं से डोमिनिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है। उसके बाद म्यांमा, होंडुरास, लीबिया, हैती, ग्रेनाडा, फिलीपीन, निकारागुआ, भारत और बहामास का स्थान है। संस्थान ने कहा कि विकासशील देश कमजोर सहन क्षमता और अनुकूलन के सीमित संसाधनों के कारण असमान रूप से प्रभावित रहे हैं।

रपट में चेतावनी दी गई है कि भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए ऐसी आपदाएं 'नई सामान्य' स्थिति बनती जा रही हैं, जिसके लिए तत्काल और अच्छी तरह से वित्त पोषित अनुकूलन उपायों की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि बढ़ती आर्थिक और मानवीय लागतें भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन योजना, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और कमजोर समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। 'थिंक टैंक' ने विश्लेषण में आंकड़ों की सीमाओं को भी स्वीकार किया और कहा कि हो सकता है कि अधूरी रिपोर्टिंग के कारण कुछ देश, विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के देशों की सही जानकारी नहीं उपलब्ध हुई हो।

Jansatta Page No-14

कर्नाटक ने भूमि अधिग्रहण मॉडल को जाना

- **अपर कृष्णा प्रोजेक्ट-3 परियोजना में बिहार मॉडल अपनाने पर विचार**
- **बिहार सरकार के अधिकारियों ने कर्नाटक की टीम को जानकारी दी**

अपीलीय प्राधिकरणों की पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की

कर्नाटक सरकार की टीम ने विशेष रूप से बिहार सरकार द्वारा 2016 में गठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अपीलीय प्राधिकरणों की पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की, जहां सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार का भूमि अधिग्रहण मॉडल सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में सशक्त उदाहरण है, जिसे अन्य राज्यों द्वारा अपनाना पूरे देश के लिए गौरव की बात है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और गति के लिए बिहार में लागू मॉडल की सफलता अब अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है। इसी क्रम में कर्नाटक सरकार ने अपर कृष्ण परियोजना (यूकेपी-3) के कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिहार के भूमि अधिग्रहण मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक दल गठित किया है।

अध्ययन दल ने बताया कि बिहार मॉडल की पारदर्शी, त्वरित और न्यायसंगत प्रक्रिया से प्रेरित होकर इसे अपर कृष्ण परियोजना में लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। टीम इस अध्ययन के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत करेगी, ताकि वहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। कर्नाटक सरकार के इस दल में केपी. मोहनराज, प्रबंध निदेशक, कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड (केबीजेएनएल) सह आयुक्त, एलएक्यू एवं आरएंडआर, बागलकोट के नेतृत्व में के. मुरलीधर कामथ, सीएस, आई. वीराबु, ईई, मारुति ब्याकोड, केएएस, प्रकाश गोपु राजपत, केएएस, एवं मोहन बी नागथन, एएसएलओ शामिल हैं। कर्नाटक की टीम पटना पहुंची और बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, सचिव गोपाल मीणा, भू-अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह तथा सहायक निदेशक आजीव वत्सराज सहित अन्य अधिकारियों ने बिहार में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया, राज्य में गठित भूमि अधिग्रहण अपीलीय प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली एवं न्यायिक ढांचे की विस्तृत जानकारी साझा की।

Hindustan Page No-9

एच-1बी वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

अमेरिका को दुनियाभर से प्रतिभाएं लानी होंगी

न्यूयार्क, 12 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा क्योंकि देश में 'कुछ खास प्रतिभाएं' नहीं हैं।

ट्रंप ने फाक्स न्यूज पर लारा इंग्राहम के साथ साक्षात्कार में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या एच-1बी वीजा का मुद्दा उनके प्रशासन के लिए एक बड़ी प्राथमिकता नहीं होगा। साक्षात्कारकर्ता ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिकी कामगारों का वेतन बढ़ाना चाहता है, तो देश में लाखों विदेशी कामगारों को नहीं आने दिया जा सकता। जवाब में ट्रंप ने कहा, 'मैं सहमत हूं, लेकिन आपको प्रतिभाओं को भी लाना होगा।' जब इंग्राहम ने कहा कि 'हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं', तो ट्रंप ने कहा, 'नहीं, आपके पास नहीं हैं। आपके पास कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं। और लोगों को सीखना होगा।'

नई वीजा नीति में बड़ा बदलाव

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर महीने में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद एच-1बी वीजा आवेदन की फीस में बड़ा इजाफा किया गया। अब नए वीजा के लिए 1,500 डालर की जगह 1 लाख अमेरिकी डालर (लगभग 83 लाख रुपए) फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर के बाद दाखिल किए गए सभी नए आवेदन या 2026 की वीजा लाटरी में शामिल होने वालों पर लागू होगा।

राष्ट्रपति ने कहा, 'आप लोगों को बेरोजगारी की कतार से हटाकर यह नहीं कह सकते कि 'मैं तुम्हें किसी कारखाने में लगा दूंगा, हम मिसाइल बनाएंगे।' उन्होंने कहा, 'जार्जिया में, उन्होंने अवैध प्रवासियों को खोजने के लिए छापे मारे। वहां दक्षिण कोरिया के लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर बैटरी बनाईं। आप जानते हैं, बैटरी बनाना बहुत जटिल है। यह कोई आसान काम नहीं है, और बहुत खतरनाक भी है। बहुत सारे विस्फोट, बहुत सारी समस्याएं।' ट्रंप ने कहा, 'उनके पास शुरुआती दौर में बैटरी बनाने और लोगों को यह काम सिखाने के लिए लगभग 500-600 लोग थे। खैर, वे चाहते थे कि वे देश से बाहर निकल जाएं।' उन्होंने कहा कि लेकिन 'आपको जरूरत पड़ेगी... मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि आप और मैं इस पर असहमत हैं।' उन्होंने कहा, 'आप यूं ही नहीं कह सकते कि कोई देश आ रहा है, एक प्लांट बनाने के लिए 10 अरब अमेरिकी डालर का निवेश करने जा रहा है और उन लोगों को बेरोजगारी की कतार से हटाने जा रहा है जिन्होंने पांच साल से काम नहीं किया है, और वे मिसाइलें बनाना शुरू करने जा रहे हैं। यह इस तरह से काम नहीं करता।'

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में दुरुपयोग की जांच के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस कार्यक्रम का उपयोग कंपनियां, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियां, अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए करती हैं।

Jansatta Page No-14

दो मरीजों की मौत के बाद फैसला, स्ट्रेन का पता लगाने के लिए मृतकों के अलावा गंभीर मरीजों के सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग होगी

डेंगू के गंभीर मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग होगी

सतर्कता

■ संजय पांडेय

पटना। पटना में डेंगू का प्रकोप नवंबर में भी लगातार बढ़ रहा है। दो मरीजों की मौत के बाद अब डेंगू के गंभीर मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग होगी। इसमें मृत दोनों मरीजों और भर्ती गंभीर मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग भी की जाएगी।

इसके पीछे डेंगू के उस स्ट्रेन का पता लगाना उद्देश्य है जिसके कारण मरीज की मौत हुई है। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए एनएमसीएच प्रशासन ने बुधवार को आईजीआईएमएस प्रशासन से बातचीत भी की है। गुरुवार को मरीजों का सैंपल आईजीआईएमएस भेजा जाएगा। एनएमसीएच के मेडिसिन विभाग के प्रमुख सह डेंगू के नोडल पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि गुरुवार को डेंगू पीड़ित के मरने की समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान इनके गंभीर होने के कारणों पर भी मेडिकल टीम चर्चा करेगी। आमतौर पर नवंबर में डेंगू का प्रकोप घटने लगता है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू से पटना में इस मौसम में कोई मौत सामने नहीं आई थी पर मरीज का गंभीर होना चिंता का कारण है।

मोहल्लों में दहशत, फॉगिंग नहीं होने का लगा रहे आरोप : एक दिन पहले एनएमसीएच में दो मरीजों की मौत के बाद लोगों में डेंगू को लेकर दहशत है। खासकर प्रभावित मोहल्लों में लोग डरे हुए हैं। नगर निगम और जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यालय को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। कहा कि फॉगिंग में उदासीनता बरती जा रही है। लार्वासाइड का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार पटना के सभी छह अंचलों में डेंगू का प्रकोप है। इस सीजन अबतक 1588 डेंगू पीड़ित मिल चुके हैं। दो लोगों की मौत भी हो गई है। सिर्फ नवंबर के 12 दिनों में अबतक 224 डेंगू पीड़ित मिले हैं। बुधवार को 21, मंगलवार को 16 और सोमवार को 12 पीड़ित मिले थे। पीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के हेड डॉ. अशोक कुमार और पारस के डॉ. प्रकाश सिन्हा ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डेंगू का प्रकोप कम है। दूसरे सप्ताह से इसकी संख्या कम होने लगेगी। देर तक बारिश होना, जगह-जगह गंदगी और जलजमाव, सब्जी मंडी-फल मंडियों में फेंके गए कचरा, डाभ नारियल में जमा पानी, खुले सीवर और नालियों से बहते पानी के कारण मच्छरों खासकर डेंगू मच्छरों के लिए अनुकूल है। इस कारण अभी तक डेंगू के मामले लगातार मिल रहे हैं।

बांकीपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद हॉट स्पॉट : पटना में बांकीपुर, पाटलिपुत्र, एनसीसी और अजीमाबाद अंचल के मोहल्ले डेंगू के लिए हॉट स्पॉट हैं। अंचलों में जलजमाव, खुले सीवर, नालियों और खाली प्लॉट में जमे पानी और गंदगी इसका बड़ा कारण है। सरकारी अस्पतालों से प्राप्त आंकड़े के अनुसार अक्तूबर के अंत तक शहर में मिले 1200 से अधिक मामले में सबसे अधिक बांकीपुर अंचल में ही पाए (509) गए हैं।

1588 मरीज मिल चुके अबतक इस सीजन डेंगू के

220 से अधिक डेंगू पीड़ित नवंबर के पहले 12 दिनों में ही मिले

■ बुधवार को 21 नए पीड़ित मिले और मंगलवार को 16, सोमवार को 12 मरीज मिले थे

अंचल- पीड़ितों की संख्या और प्रभावित मोहल्ले (हॉट स्पॉट)

- **बांकीपुर**- 509- मुसल्लहपुर हाट, सुल्तानगंज, मछुआटोली, बाजार समिति, संदलपुर भिखना पहाड़ी, कदमकुआं, महेंद्रू, रामपुर रोड, खजांची रोड।
- **पाटलिपुत्र अंचल**- 259- बोरिंग रोड, राजाबाजार, राजापुर पुल, आशियाना, इन्द्रपुरी, दीघा घाट, एजी कॉलोनी, एसकेपुरी, शेखपुरा, मंदिरी, आशियाना नगर।
- **पटना सिटी** : 43 - खाजेकलां, मालसलामी।
- **नूतन राजधानी अंचल**- 114 : तारामंडल, सिपारा, अनीसाबाद, मीठापुर
- **अजीमाबाद**-110 : अगमकुआं, एनएमसीएच के आसपास के मोहल्ले, बजरंगपुरी, गुलजारबाग, आलमगंज, गुड़ की मंडी, संदलपुर, गायघाट।
- **कंकड़बाग** - 92 : कुम्हरार, भागवतनगर, हनुमाननगर, संजय नगर, आरएमएस कॉलोनी, पोस्टल पार्क, भूतनाथ रोड, जगनपुरा, रामकृष्णानगर, चिरैयाटांड

क्या है जीनोम सिक्वेंसिंग : डेंगू वायरस के आनुवंशिक कोड (जीनोम) का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि वायरस कैसे विकसित होता है, फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। इसके माध्यम से वायरस के विभिन्न प्रकारों, उत्परिवर्तनों और भौगोलिक प्रसार को ट्रैक किया जाता है, जिससे महामारी की निगरानी, स्रोत का पता लगाने और संभावित नई दवा या वैक्सीन विकसित करने में मदद मिले।

पटना में 1092 पुरुष और 496 महिलाएं डेंगू पीड़ित

पटना में मिले कुल 1588 डेंगू पीड़ितों में 1092 पुरुष और 496 महिलाएं डेंगू पीड़ित हुई हैं। वहीं आयुवर्ग में सबसे अधिक पीड़ित 21 से 30 वर्ष आयुवर्ग के (कुल 609) युवा हैं। इसके बाद 11 से 20 आयुवर्ग के 369, 31 से 40 वर्ष आयुवर्ग के 213, 41 से 50 आयुवर्ग के 123, 51 से 60 आयुवर्ग के 90, 61 सल से अधिक आयुवर्ग के 83, और 0-10 वर्ष आयुवर्ग के 101 बच्चे भी डेंगू से पीड़ित हैं।

सरकारी अस्पतालों में 1214 और निजी में 374 मरीज मिले

पटना में अबतक सरकारी अस्पतालों में 1214 और निजी अस्पतालों और जांच लैबों में 374 पीड़ित मिले हैं। इनमें पीएमसीएच में 514, एनएमसीएच में 307, एम्स में 55, आरएमआरआई में 43 एनजीआरएच में 244, आईजीआईएमएस में 35 और एलएनजेपी में 16 पीड़ित मिले हैं। जयप्रभा मेदांता में 67, पारस में 49, मेडिवर्सल में 33, कुर्जी में 52, एशियन सिटी में 10, साई में सात, फोर्ड में चार और सहयोग में एक पीड़ित का इलाज हुआ है। निजी जांच लैबों में सेन में 57, गीतांजलि में 12, लाल पैथ में 37, टाटा 1 एमजी में 38 और प्रभात में सात पीड़ित मिले हैं।

Hindustan Page No-3

अक्टूबर में खुदरा महंगाई 10 सालों में सबसे कम

जीएसटी दरों में कमी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से 0.25% पर आई मुद्रास्फीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जीएसटी दरों में कमी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से अक्टूबर माह की खुदरा महंगाई दर 0.25 प्रतिशत के साथ पिछले 10 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई। दस साल पहले महंगाई दर मापने के लिए नए आधार वर्ष (2012) को लागू किया गया था और नए आधार वर्ष के तहत यह सबसे कम महंगाई दर है।

अक्टूबर महीने में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर में पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 5.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस साल सितंबर में खुदरा महंगाई दर 1.44 प्रतिशत थी और इस प्रकार सितंबर माह के मुकाबले अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर में 119 आधार अंक की कमी आई। खुदरा महंगाई दर में लगातार नरमी को देखते हुए एक बार फिर से आर्थिक जानकार दिसंबर में आरबीआइ की तरफ से बैंक दर में कटौती की संभावना जाहिर करने लगे हैं। आरबीआइ ने खुदरा महंगाई दर की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत तो न्यूनतम दो प्रतिशत तय कर रखा है। आरबीआइ को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआइ अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। जीएसटी की घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हुई हैं। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति घटी है और यह क्रमशः 0.25 प्रतिशत और 0.88 प्रतिशत रही। महंगाई दर में यह गिरावट उल्लेखनीय है।

- खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में पिछले साल के मुकाबले 5.02 प्रतिशत की गिरावट
- विशेषज्ञ आरबीआइ की तरफ से बैंक दर में कटौती की संभावना करने लगे हैं जाहिर

खाद्य तेल के दाम में पहले की तरह मजबूती का रुख

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं में सब्जी के खुदरा दाम में पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 27.57 प्रतिशत, दाल में 11.17 प्रतिशत तो मसाले में 3.29 प्रतिशत की गिरावट रही। जीएसटी में कटौती से विभिन्न प्रकार के प्रोसेस्ड फूड की खुदरा महंगाई दर में भी 3.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि खाद्य तेल के दाम में पहले की तरह मजबूती का रुख जारी है।

केरल में महंगाई दर 8.56 प्रतिशत पर रही

देश की खुदरा महंगाई दर मात्र 0.25 प्रतिशत रह गई है, लेकिन केरल में अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर 8.56 प्रतिशत रही। जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर 2.95 प्रतिशत, कर्नाटक में 2.34 प्रतिशत, पंजाब में 1.81 प्रतिशत तो तमिलनाडु में 1.29 प्रतिशत दर्ज की गई। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व गुजरात जैसे राज्यों में खुदरा महंगाई दर 0.5-1.97 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

"यह स्थिति अक्टूबर, 2025 के नीति दस्तावेज के नरम रुख के साथ, दिसंबर, 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती का समर्थन करेगी। यह स्थिति तबतक बनी रहेगी जब तक कि वित वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से ऊंची न रहे।

-अदिति नायर, मुख्य अर्थशास्त्री, इक्रा

मौद्रिक नीति के नजरिये से, मुद्रास्फीति में नरमी आरबीआई को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देने के लिए ज्यादा गुंजाइश देती है। हालांकि, बाहरी चुनौतियां और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।"

-रजनी सिन्हा, मुख्य अर्थशास्त्री, केयरएज रेटिंग्स

अक्टूबर में वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर	
अनाज	0.92 प्रतिशत
मांस-मछली	1.74 प्रतिशत
फल	6.69 प्रतिशत
खाद्य तेल	11.17 प्रतिशत
कपड़े व फुटवियर	1.70 प्रतिशत
बिजली व अन्य ईंधन	1.98 प्रतिशत
ट्रांसपोर्ट व संचार	0.94 प्रतिशत
मनोरंजन	1.46 प्रतिशत
किस राज्य में कितनी रही महंगाई	
दिल्ली	(-0.34) प्रतिशत
बिहार	(-1.97) प्रतिशत
छत्तीसगढ	(-1.20) प्रतिशत
झारखंड	(-0.51) प्रतिशत
उत्तराखंड	0.88 प्रतिशत
हरियाणा	(-0.51) प्रतिशत

Dainik Jagaran Page No-11

राजधानी में समनपुरा तो प्रदेश में हाजीपुर की हवा अधिक प्रदूषित

निर्माण कार्य, सड़कों की ठीक से सफाई नहीं होना प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण

जागरण संवाददाता, पटना : ठंड में वृद्धि होने के साथ ही प्रदेश की हवा भी प्रदूषित होने लगी है। बुधवार को पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) मंगलवार की तुलना में कम रहा। मंगलवार को एक्यूआइ 196 था, जबकि बुधवार को 164 दर्ज किया गया। राजधानी में सबसे प्रदूषित हवा समनपुरा का 225 एक्यूआइ रहा, जबकि प्रदेश में सबसे प्रदूषित हाजीपुर रहा। वहां का एक्यूआइ 187 रिकार्ड किया गया। वहीं, प्रदेश में आरा की हवा स्वच्छ रही, जहां का एक्यूआइ 49 दर्ज किया गया। राजधानी के समनपुरा में प्रदूषण बढ़ने का कारण निर्माण कार्य, सड़कों की ठीक से सफाई न होना है। इसके कारण सड़क किनारे धूल की मोटी परत जमा हो जाती है। मौसम विज्ञानी के अनुसार, गर्मी की तुलना में सर्दी के दिनों में वायु प्रदूषित होना आम बात है। सर्दी में तापमान कम होने के कारण हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में भारी होती है और नीचे की ओर आती है। इससे हवा की गति कम हो जाती है और प्रदूषित तत्व हवा में ही फंसे रह जाते हैं। सर्दियों में हवा में नमी कम होती है। नमी प्रदूषित कणों को आपस में चिपकाने में मदद करती है और उन्हें जमीन पर गिरने में मदद करती है, लेकिन जब नमी कम होती है तो प्रदूषक कण हवा में तैरते हैं। सर्द दिनों में धुंध और कोहरे छाना आम है। ये प्रदूषक कणों को अपने अंदर समेट लेते हैं और हवा में घुल मिल जाते हैं।

गंगा किनारे जेपी गंगा पथ पर छाई धुंध। नवंबर में ठंड बढ़ने के साथ हवा भी प्रदूषित होने लगी है ● जागरण

187 एक्यूआइ के साथ प्रदेश में सबसे खराब हवा हाजीपुर का

49 एक्यूआइ के साथ आरा की हवा सबसे स्वच्छ

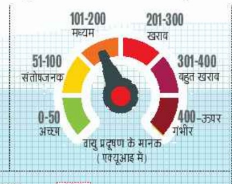

164 एक्यूआइ रिकार्ड किया गया पटना के समनपुरा इलाके का

प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति

सांस लेने में तकलीफ आंखों में जलन व गले में खराश की शिकायतें

जागरण संवाददाता, पटना : राजधानी की हवा फिर जहरीली हो गई है। शहर की फिजा में घुलते धुएं और धूलकण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही धुंध की चादर छाई रही और कई इलाकों में दृश्यता कम होने के साथ लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें होने लगीं। डाक्टरों का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और पहले से अस्थमा या श्वसन रोग से पीड़ित मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। एम्स के प्लमोनरी विभाग के वरीय प्राध्यापक डा. सौरभ करमाकर ने बताया कि पिछले दो दिनों में सांस फूलने और खांसी-जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या करीब 25-30 प्रतिशत तक बढ़ी है। प्रदूषण के कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है, जिससे अस्थमा और हृदय रोगियों की स्थिति और गंभीर हो सकती है। आइजीआइएमएस के बाल रोग विशेषज्ञ डा. रिजवान अहमद ने कहा कि बच्चे बाहर खेलने के बाद खांसी और आंखों में जलन की शिकायत लेकर आ रहे हैं। स्वजनों को चाहिए कि वे बच्चों को सुबह-शाम बाहर नहीं निकलने दें। इसके साथ ही घर में एयर प्यूरिफायर या मास्क का उपयोग करें ताकि प्रदूषण से बचा जा सके।

पटना सहित 19 जिलों के तापमान में वृद्धि, सुबह में धुंध का प्रभाव

28.1 डिग्री सेल्सियस रहा पटना का तापमान

31.0 डिग्री मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान

प्रमुख शहरों का तापमान

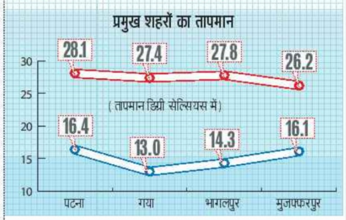

जासं, पटना : प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह-शाम हल्की धुंध और ओस के साथ ठंड का प्रभाव बना हुआ है। जबकि, दिन के समय सूरज की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे माह सुबह-शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने बताया कि दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने के साथ कड़ाके की ठंड में वृद्धि के आसार हैं। बीते वर्ष दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने के कारण सर्दी में ज्यादा ठंडक नहीं महसूस हुई थी। प्रदेश में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ जाती है लेकिन दिन के समय में तापमान सामान्य से अधिक रहता है। यह उतार-चढ़ाव धूप, हवा की गति और स्थानीय नमी पर निर्भर करता है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 28.1डिग्री सेल्सियस एवं 31.0 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को पटना सहित 19 जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना व आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध का प्रभाव एवं सुबह-शाम सिहरन की स्थिति बनी रही।

दावा : दिमाग में पहुंचकर इलाज करेगी नई चिप

मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाई खास चिप

सेहत

- ये चिप रक्तप्रवाह में तैरते हुए मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से तक खुद पहुंच जाएगी
- मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहद सरल बना सकता है यह नया प्रयोग

कैंब्रिज, एजेंसी। आने वाले समय में मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का इलाज बेहद सरल हो जाएगा। वैज्ञानिक अब इंजेक्शन से लगने वाली ऐसी चिप बना रहे हैं, जो दिमागी रोग का इलाज करेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे सिर की सर्जरी करने की भी जरूरत नहीं होगी।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता इसी सपने को हकीकत में बदलने पर काम कर रहे हैं। वे बहुत छोटे, बिना तार वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बना रहे हैं, जो रक्त में तैरते हुए मस्तिष्क के उस हिस्से तक पहुंच सकते हैं, जहां इलाज की जरूरत है। चिप्स इतने सूक्ष्म हैं कि इनकी लंबाई चावल के एक दाने के अरबवें हिस्से के बराबर होती है। चूहों पर किए गए प्रयोग में, पाया गया कि ये चिप्स बिना किसी मानवीय मार्गदर्शन के मस्तिष्क के सही और विशिष्ट स्थान को ढूंढ सकती हैं और वहां खुद ही स्थापित हो सकती हैं।

कैसे काम करेंगे चिप्स : एक बार मस्तिष्क में स्थापित होने के बाद ये चिप बिजली की हल्की उत्तेजना देगी। आज भी पार्किंसंस, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मिर्गी और यहां तक कि गंभीर अवसाद जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ऐसी ही उत्तेजना का उपयोग किया जाता है, पर अभी इसके लिए बड़ी और महंगी सर्जरी की जरूरत होती है। चिप को इंजेक्ट करने से पहले जैविक कोशिकाओं से जोड़ा जाता है। ये कोशिकाएं इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरह छिपा देती हैं कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उन पर हमला नहीं करती और उपचार शुरू हो जाता है।

भविष्य की उम्मीद

यह तकनीक केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। भविष्य में इसे शरीर के अन्य हिस्सों में बीमारियों का इलाज करने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। यह चिकित्सा जगत में नई क्रांति साबित हो सकती है, जहां बिना सर्जरी के रोगों का इलाज संभव होगा।

Hindustan Page No-18

निर्यातकों को अब बिना गारंटी ऋण मिलेगा

कैबिनेट बैठक

20 हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी

- अश्विनी वैष्णव बोले, कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, समुद्री और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 45 हजार 60 करोड़ से अधिक के कई आर्थिक निर्णयों को मंजूरी दी। इनमें 25 हजार करोड़ की निर्यात प्रोत्साहन मिशन और 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना शामिल है।

इस योजना के तहत अब छोटे और मध्यम उद्योगों सहित योग्य निर्यातकों को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों के संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया, इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए निर्यातकों को 100% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इसका मतलब है, यदि कोई निर्यातक ऋण लेता है और किसी वजह से उसे चुका नहीं पाता तो सरकार उसकी गारंटी लेगी। वर्तमान में निर्यात आधारित उद्योगों में सीधे और परोक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का योगदान लगभग 45 प्रतिशत है।

निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी: केंद्र ने 25,060 रुपये के व्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी। यह मिशन इस वित्त वर्ष से शुरू होगा और छह वित्त वर्ष के लिए होगा। इस मिशन को दो उपयोजनाओं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके जरिए कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, समुद्री व रत्न -आभूषण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

खनिजों पर रॉयल्टी : सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे अहम खनिजों पर रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के इस फैसले से सीजियम, रुबिडियम, जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल इन खनिजों को, बल्कि इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को भी लाभ मिलेगा।

जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी के 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसमें निजी खपत वृद्धि प्रमुख चालक होगी। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की वास्तविक जीडीपी के चालू वित्त वर्ष में पांच तिमाहियों में सबसे तेज गति से 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

भारत में तेल की मांग तेजी से बढ़ेगी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बुधवार को कहा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता देश, भारत अगले दशक में तेल की मांग में वृद्धि का नया केंद्र होगा। उभरते बाजारों और वस्थाओं में, भारत में ऊर्जा की मांग सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसका 2035 तक हर साल औसतन तीन प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

अक्तूबर में खुदरा महंगाई 10 साल के निचले स्तर पर पहुंची

जीएसटी दरों में कटौती से नरम पड़ी महंगाई

रिपोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। खुदरा महंगाई दर में आई तेज गिरावट के पीछे 22 सितंबर को गई जीएसटी कटौती का भी अहम योगदान है। इसका सही मायनों में असर अक्तूबर की महंगाई में देखने को मिला है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों में यह तस्वीर साफ हुई है।

इस अवधि में तेल-घी, सब्जियां, फल, अंडे, अनाज, जूते-चप्पल और परिवहन सेवाओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इन्हीं कारणों के चलते खुदरा महंगाई में सितंबर के मुकाबले 119 और खाद्य महंगाई में 269 अंकों की कमी आई है। सितंबर में खुदरा महंगाई 1.44 प्रतिशत और खाद्य महंगाई दर -2.33 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर -0.25% रही है, जो सितंबर में 1.07 फीसदी रही थी। शहरी महंगाई दर 1.83 से घटकर 0.88 फीसदी पर आ गई। अक्तूबर 2025 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से जीएसटी में गिरावट, अनुकूल आधार प्रभाव और तेल एवं वसा, सब्जियां, फल, अंडे, जूते, अनाज और उत्पाद, परिवहन और संचार आदि की मुद्रास्फीति में गिरावट के पूरे महीने के प्रभाव के कारण है।

खाद्य वस्तु और उनकी कीमतों में गिरावट

उत्पाद	गिरावट (प्रतिशत)
सब्जियां	-27.57
दालें	-16.15
प्याज	-54.31
टमाटर	-42.93
आलू	-36.65
तेल और घी	-11

जनवरी 2015 के बाद सबसे कम

सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2015 में आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित कर 2012=100 किया था, जिसके बाद इसे लागू किया गया। लागू होने की तिथि के हिसाब से जनवरी 2015 के बाद महंगाई निचले स्तर पर दर्ज की गई है।

ब्याज दरों में हो सकती है कटौती

लगातार चार महीने से महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान चार फीसदी के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। इसका मतलब है कि कीमतों में कमी के बीच लोगों की जेब पर खर्चों का बोझ कम हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय बैंक आने वाले मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला कर सकता है।

इनके दामों में हुई बढ़ोतरी

सोना	57.83%
चांदी	62.36%

केरल में सबसे अधिक महंगाई

अक्तूबर में देश के सबसे अधिक महंगाई वाले पांच राज्यों में केरल सबसे अव्वल है। जहां पर महंगाई 8.56 प्रतिशत रही।

ई-कॉमर्स के अस्थायी कर्मी भी एनपीएस में शामिल हो सकेंगे

पहल

नई दिल्ली, एजेंसी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और ऐप आधारित मंचों से जुड़े कामगारों (गिग वर्कर) को भी एनपीएस के तहत पेंशन सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 'एनपीएस ई-श्रमिक योजना' की शुरुआत की है। जो कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं, वे सीधे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

पेंशन नियामक संस्था पीएफआडीए के अनुसार, इस योजना का मकसद उन श्रमिकों को पेंशन कवरेज देना है, जो किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन रोज़गार के लिए प्लेटफॉर्म सेवाओं के माध्यम से काम करते हैं। अभी तक ऐसे 'गिग वर्कर' के लिए कोई तय पेंशन व्यवस्था नहीं थी। अब एनपीएस ई-श्रमिक मॉडल से उन्हें भी नियमित पेंशन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले एक साल में 10 करोड़ से अधिक गिग और असंगठित श्रमिकों को इस योजना से जोड़ने का है।

इनके लिए योजना : इस पेंशन योजना में सभी गिग वर्कर यानी ऐप आधारित मंचों पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, ट्यूटर या फ्रीलांसर आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क है और सालाना शुल्क केवल 15 रुपये रखा गया है। इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु तक के लोग शामिल हो सकते हैं।

कितना योगदान

न्यूनतम योगदान 99 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य एनपीएस योजना में यह 500 रुपये होता है।

ई-श्रम पोर्टल से जुड़े हों

यह सुविधा उन श्रमिकों और कामगारों के लिए खुली है, जो पहले से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। वे सीधे पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन श्रमिकों का पंजीकरण अब तक नहीं हुआ है, पहले उन्हें ई-श्रम कार्ड बनवाना होगा।

ऐसे होगा योगदान

योजना में तीन तरीके से योगदान किया जा सकता है। पहला, संयुक्त ज्वाइंट योगदान, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों मिलकर योगदान करेंगे। दूसरा विकल्प में केवल कर्मचारी को ही योगदान करना होगा।। तीसरे विकल्प में केवल कंपनी ही योगदान कर सकती है।

ऐसे करें आवेदन

- वेबसाइट (www.eshram.gov.in) पर जाएं। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लॉगिन करें।
- **NPS for Unorganised Workers** सेक्शन पर क्लिक करें। **PRAN** नंबर बनवाने के लिए नाम, पता, पैन नंबर और बैंक खाता आदि जानकारी भरनी होगी।
- उसके बाद आपको महीने में जमा करने की राशि भरनी होगी।
- अब सबमिट करने के बाद आपका **PRAN** नंबर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

क्या है एनपीएस

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) केंद्र सरकार द्वारा द्वारा संचालित एक सेवानिवृत्ति योजना है। इसमें हर महीने एक तय राशि जमा करने पर 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाती है। एनपीएस को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2009 में इसे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया था। अब इसे गिग वर्करों के लिए भी शुरू किया गया है। इसे पीएफआरडीए की ओर से संचालित किया जाता है।

नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य

बता दें कि इस योजना में शामिल वर्कर को 60 वर्ष की उम्र के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलेगी। यदि बीच में कोई अप्रत्याशित स्थिति आती है, तो नॉमिनी को रकम का लाभ दिया जाएगा। नॉमिनी की विवरण देने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा।

Hindustan Page No-13

बिहार को कृषि क्षेत्र में दो अवार्ड मिले

भागलपुर। बिहार कृषि विवि सबौर के मार्गदर्शन में बुधवार को बिहार के खाते में कृषि के क्षेत्र में दो अवार्ड मिले हैं। इसमें मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, पूर्णिया को मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही बीएयू से जुड़े रोहतास के किसान नकुल सिंह को खीरमोहन धान के लिए पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली में पीपीवी एवं एफआरए (प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एंड फर्मर्स राइट्स अथॉरिटी) के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दिया गया। यह पुरस्कार कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय राज्य मंत्रियों भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर की उपस्थिति में प्रदान किया। बीएयू के कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह ने कहा कि संघ व नकुल सिंह की यह उपलब्धि बिहार के किसानों और मखाना उत्पादकों के लिए एक प्रेरणा है।

Hindustan Page No-12

अनुलोम-विलोम
व्हाइट कॉलर आतंकवाद

व्हाइट कॉलर आतंकवाद एक नई चुनौती

दिल्ली धमाके की गूंज अब तक शांत नहीं हुई है। इस मामले में जितने भी संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उनमें से अधिकतर पढ़े-लिखे लोग हैं। यही कारण है कि इसे 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल' कहा जा रहा है। आखिर क्या है व्हाइट कॉलर आतंकवाद? दरअसल, इसका तात्पर्य उन आतंकियों से है, जो पढ़े-लिखे और पेशेवर हैं। इनमें कोई डॉक्टर होता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई प्रबंधन क्षेत्र का पेशेवर। कहने को तो ये पढ़े-लिखे और डिग्रीधारक होते हैं, लेकिन इनका असली काम आतंकवाद फैलाना और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना है। दिल्ली धमाके में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें डॉक्टर अधिक हैं। इनके तार दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक हैं, जिसका मतलब है कि पूरे देश में व्हाइट कॉलर आतंकियों का नेटवर्क बढ़ रहा है।

आमतौर पर यह धारणा रही है कि गरीबी व अशिक्षा से ही आतंकवाद का जन्म होता है और आतंकी मूलतः गरीब या अशिक्षित होते हैं। व्हाइट कॉलर आतंकवाद इस धारणा को तोड़ता है। इन दहशतगर्दों को आतंकी संगठनों का 'बैकबोन' माना जाता है। हथियार उठाकर किसी हमले या आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान आसान होती है, लेकिन पीठ पीछे उनकी मदद करने वाले पढ़े-लिखे इन अराजक तत्वों की पहचान काफी मुश्किल। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं, जानकारी व संदेश एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, फंड जुटाते हैं और पूरे आतंकी संगठन को चलाने में मदद करते हैं। इस तरह, जो ढांचा ये तैयार करते हैं, उसे बहुत मजबूत माना जाता है। आजकल यह प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है, क्योंकि आतंकी संगठनों के भीतर यह धारणा होती है कि पढ़े-लिखे आतंकी दहशतगर्दी को नया आयाम दे सकते हैं। इनकी शिक्षा-दीक्षा का इस्तेमाल किसी आम इंसान को 'भ्रमित करने' में किया जा सकता है और उसके जरिये आतंकवाद फैलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसे आतंकियों का आम जनमानस पर प्रभाव पड़ता है।

एक बात तो तय है कि दिल्ली धमाके में जितने भी लोग पकड़े जाएंगे, उनमें से अधिकतर व्हाइट कॉलर ही होंगे। मुमकिन है कि इनके आका पाकिस्तान में बैठे हों और संचार के आधुनिक साधनों की मदद से इन लोगों के मन में जहर भर दिया गया हो। अब हमारी खुफिया एजेंसियों को सिर्फ आतंकवाद से नहीं लड़ना है, बल्कि उसके उन्नत रूप 'व्हाइट कॉलर आतंकवाद' से भी लड़ना है। भले ही, इन पढ़े-लिखे आतंकियों की पहचान कठिन हो, लेकिन उम्मीद यही है कि हमारी एजेंसिया इनको समय रहते पकड़ने में कामयाब होंगी।

अमित बैजनाथ गर्ग, टिप्पणीकार

पहले भी पढ़े-लिखे लोग बने आतंकी

'व्हाइट कॉलर आतंकवाद' कोई नया ट्रेंड नहीं है। यह परिपाटी वर्षों से देखी जा रही है, जिससे सुरक्षा और खुफिया बल लगातार लड़ भी रहे हैं। बीते दो-तीन दशकों में ही देश-दुनिया में न जाने कितने ऐसे युवा आतंकी पकड़े गए हैं, जो न सिर्फ उच्च शिक्षित थे, बल्कि वेश-भूषा या रहन-सहन से उनको आसानी से पहचान पाना कठिन था। माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट ने ऐसे आतंकियों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। उसने विकसित देशों तक में अपने नेटवर्क इस तरह बढ़ाए कि 'पढ़े-लिखे' (हालांकि मैं इसे पढ़ा-लिखा नहीं मानता, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति विनयशील होता है) भ्रमित नौजवान उसकी ओर खींचे चले गए। भारत में ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें शिक्षित नौजवान भ्रमित होकर आतंकी संगठनों में शामिल हो गए।

हालांकि, मामला सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। भारतीय संसद पर हुए हमले में जिस अफजल गुरु को फांसी हुई, वह मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर आतंकी बना था। उस पर तो कई अन्य नौजवानों को बरगलाने का भी आरोप था। इसी तरह, कंधार विमान अपहरण कांड में, जिस उमर सईद शेख को विमान अपहरणकर्ताओं ने छुड़वाया, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर चुका है। खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को कौन नहीं जानता? वह भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था। ये तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो देश-दुनिया में चर्चित हैं। कई नाम तो गुपचुप तरीके से अपनी नापाक मंशा में जुटे होंगे। ऐसे लोग या तो किसी धर्मगुरु के संपर्क में आने के बाद आतंकी बनते हैं या फिर इंटरनेट पर जेहादी सामग्रियों को देखकर या फिर उनमें मजहबी उन्माद इस कदर भर दी जाती है कि अच्छे और बुरे की परख उनमें खत्म हो जाती है। मेडिकल या इंजीनियरिंग या उच्च शिक्षा पाने वाले आतंकियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे प्रताड़ित थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। वे चाहते, तो खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। फिर भी, उन्होंने आतंकवादी बनना कुबूल किया, और अपना जीवन नरक बना लिया।

हमें समझना होगा कि जेहाद एक वैचारिक आंदोलन है और किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने में पढ़ा-लिखा तबका ज्यादा कारगर होता है। संभवतः इसीलिए आतंकी संगठनों की नजरें काफी पहले से उच्च शिक्षित नौजवानों पर रही हैं। वे जीवन मूल्यों की मनमाफिक व्याख्या करके इनको भ्रमित कर देते हैं। ऐसे में, हमारी सरकारों के सामने दोहरी चुनौती है। उनको दहशतगर्दी भी रोकनी है और नौजवानों को भ्रमित होने से बचाना भी है।

कुणाल श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

थकते कदम

अशोक कुमार

धरती पर जीवन के पदार्पण होते ही वह कई चरणों में अपनी यात्रा की शुरुआत कर देता है। शैशवास्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था के दौर में मानव मन कई अनुभूतियों और कार्यों से अपने को संलिप्त रखने को विवश है। बचपन के बाद तरुण काल में उसे विद्यालय के प्रांगण आमंत्रित कर लिया जाता है। जीवन निर्माण के उद्देश्य में व्यक्ति आगे की कड़ियों से तादात्म्य स्थापित करते हुए अध्ययन, व्यवसाय, खेती-गृहस्थी, नौकरी और अन्य प्रकल्पों की पूर्णता के बाद एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर आकर ठहर जाता है, जब वह अपने सभी बुनियादी दायित्वों से भी आजाद हो जाता है। इस क्रम में पुत्री-पुत्र की शादी के बाद नवदंपति के लिए नूतन घर गृहस्थी के नए आयाम प्रकट होते हैं। जीवन के उत्तरार्ध काल में माता-पिता जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, तब उनके पास अपनी एक सक्रिय दिनचर्या नहीं होती।

इस दौर में परिवार के सदस्य शिशु के आगमन की बाट जोहते हैं और जब यह घड़ी आ जाती है तो बच्चे के माता-पिता के साथ उसके दादा-दादी, नाना-नानी के जीवन में आनंद की लहरें उफान पर होती हैं। इस स्थिति में बुजुर्गों की दुनिया पूरी तरह परिवर्तित होते दिखती है। मासूम की मुस्कान और उसे अपनी गोद में लेकर स्नेह सिंचित करने का पल बुजुर्गों को नैसर्गिक सुख की अनुभूति से लबालब भर देता है। धीरे-धीरे शिशु अपनी उम्र के उस मोड़ पर आ जाता है, जब वह अपने पैरों पर खड़ा होना, ठुमकते हुए चहलकदमी करना कुछ बुदबुदाना और घर के सभी सदस्यों को पहचानने की अल्प समझ से जुड़ता है। माता-पिता के साथ बिताए पलों के बाद बच्चे का शेष समय उसके नानी-दादी, दादा-नाना के साथ अधिक बीतता हैं। ये लोग भी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं कि कब उन्हें नन्हे बच्चे को अपने पास रखने का मौका मिले।

कई बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुभव का सारांश है कि बुजुर्ग जब अपने पोते-पोती, नाती-नतिनी की बाल्यावस्था की गतिविधियों से बंध जाते हैं, तो उनकी उम्र बढ़ने की गति कम होने लगती है। वे आत्मिक संतुष्टि और सुख के दृश्यों को जब नित्य जीते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के सूचकांक में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज होती है। इस अवस्था में वे अपने स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्याओं को भूल जाते हैं, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य बच्चों के साथ समय बिताना तय है। यह घड़ी उन्हें अकेलेपन से राहत दिलाते हुए खुश रखती है। बच्चों के साथ बुजुर्गों के भावनात्मक लगाव के कुछ अन्य सकारात्मक लाभ भी मिलते हैं, जैसे जीवन के अन्य सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर वे स्वच्छंद वातावरण में बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करते हैं। इससे उनकी प्रसन्नता और उत्साह में वृद्धि करने वाले हार्मोन का प्रवाह भी बना रहता है। बढ़ती उम्र का तकाजा है कि बुजुर्गों के शरीर में कुछ न कुछ व्याधियां प्रवेश कर जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं- मधुमेह, रक्तचाप, कैल्शियम की कमी। इस कारण से वे अपने रोग के निदान के लिए अधिक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जब उनके पोते-पोती, नाती-नतिनी अपने कदमों में गति भरने लगते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है, जिसका मूल आधार बुजुर्ग बनते हैं।

बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के फलस्वरूप बुजुर्गों का अधिक चलना-फिरना हो जाता है। घर के आंगन या आसपास किसी उद्यान में बच्चों को ले जाकर उसके साथ खेलना, उसके पीछे अपनी गति में दौड़ने जैसी अन्य गतिविधियां उन्हें सक्रिय रखती हैं। शाम के समय बच्चों को कहानियां सुनाने और कभी-कभी अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने से बच्चे बुजुर्गों की ओर आकर्षित रहते है। कभी गांव में बुजुर्ग बच्चों को अपनी पीठ और कंधों पर बिठाकर कुछ देर घुमा दिया करते थे, जबकि दोनों घुटनों पर उन्हें सवार कर झुला झुलाने (घुघा-मामा) से बच्चों का मधुर मनोरंजन हुआ करता था। इस प्रक्रिया से बुजुर्गों को लाभप्रद व्यायाम हो जाता था।

बच्चों की देखभाल में सम्मिलित लोग अन्य बुजुर्गों की तुलना में कम सुस्त होते हैं। यह सक्रियता बुजुर्गों के शारीरिक वजन को नियंत्रित करते हुए उनके स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। अकेलेपन के शिकार अधिकतर बुजुर्ग अक्सर गैरजरूरी विषयों की चिंतन की गंभीरता के चलते मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनकी रोचक सहभागिता इस रोग से रक्षा करती है। आज की भौतिक भागदौड़ में अधिकांश बुजुर्ग अनिद्रा से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब वे बच्चों की किलकारियां सुनते हैं, उसकी मधुर मुस्कान देखते हैं, उनके साथ खेल-खेल में अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो उन्हें भरपूर नींद भी आती है और वे रोज सुबह तरोताजा महसूस करते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **एकल परिवार की बहुलता के कारण बहुत से घरों में बुजुर्ग अकेले भी हैं, जिन्हें समय बिताना कठिन हो जाता है। बुजुर्ग दंपति तो आपस में कुछ बोल-बतिया कर समय काट भी लेते हैं, लेकिन जिस घर में बुजुर्ग सिर्फ अकेले हो गए हैं, उन्हें एकाकीपन और निष्क्रियता घेर लेती है।**

एकल परिवार की बहुलता के कारण बहुत से घरों में बुजुर्ग अकेले भी हैं, जिन्हें समय बिताना कठिन हो गया है। बुजुर्ग दंपति तो कुछ आपस में बोल-बतिया कर समय काट भी लेते हैं, लेकिन जिस घर-आंगन में बुजुर्ग सिर्फ अकेले हो गए हैं, उनके पुत्र-पुत्री साल में एक दो बार आते हैं और वे अपने माता-पिता को कई कारणों से साथ रख नहीं पाते। ऐसे बुजुर्गों के जीवन को एकाकीपन और निष्क्रियता घेर लेती है। उनकी मानसिक व्यथा के घनत्व में अधिक वृद्धि तब दिखती है जब पर्व-त्योहार में उनकी संतान दो-चार दिन के लिए भी घर नहीं आ पाते। आज की युवा पीढ़ी को इस संदर्भ में विशेष चिंतन-मनन करना चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में जब आएंगे, तब तक पूर्वजों द्वारा संकल्पित ताने-बाने बिखरने का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए समय रहते अकेलेपन में जी रहे बुजुर्गों के कदमों में गति कायम रखने की हर कोशिश की जाए। शायद इस चेष्टा का फल यह हो कि हमारे बुजुर्गों की जिजीविषा जीवंत हो उठे।

सेवा निर्यात का बढ़ता दायरा

भारत ने वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3 फीसद की हिस्सेदारी के साथ अब दुनिया में सातवां स्थान हासिल कर लिया है। पिछले वित्त वर्ष में देश का सेवा निर्यात 387.5 अरब डालर था, जो चालू वित्त वर्ष के अंत तक 475 अरब डालर तक पहुंच सकता है।

जयंतीलाल भंडारी

भारत सेवा निर्यात में भले ही नई ऊंचाई हासिल करते हुए वैश्विक सेवा निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर इस मामले में उसके सामने चुनौतियां भी कम नही हैं। इनमें सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, सभी क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने, ग्रामीण और छोटे शहरों में शोध एवं नवाचार के साथ-साथ युवाओं में कृत्रिम मेधा (एआइ) जैसे कौशल विकसित करने की चुनौतियां प्रमुख हैं। इनके साथ-साथ अमेरिका की नई शुल्क नीति और वीजा चुनौतियां भी भारत के सेवा निर्यात की राह में मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इन चुनौतियों के बीच भारत अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल विकास और डिजिटल क्षेत्र में शिक्षित-प्रशिक्षत करके उसे सेवा निर्यात में सहभागी बनाने की संभावनाओं को साकार रूप दे सकता है।

पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 387.5 अरब डालर रहा था। उम्मीद है कि यह चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 475 अरब डालर की रेकार्ड नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2013-14 में भारत के सेवा निर्यात का आकार महज 152 अरब डालर था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के मुताबिक, भारत ने वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3 फीसद की हिस्सेदारी के साथ अब दुनिया में सातवां स्थान हासिल कर लिया है। वर्ष 2001 में सेवा निर्यात के मामले में भारत 24वें स्थान पर था। यह उपलब्धि मुख्य रूप से दूरसंचसार, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य सेवाओं की बदौलत संभव हो पाई है। ये क्षेत्र देश के कुल सेवा निर्यात का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा रखते हैं। इनके साथ-साथ भारत सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवा निर्यात में भी आगे हैं।

सेवा निर्यात की मौजूदा प्रगति देश में हो रहे संरचनात्मक सुधारों, तकनीकी विकास और नई पीढ़ी की उच्च कौशल युक्त क्षमताओं का परिणाम है। गौरतलब है कि सेवा निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, बैंकिंग, वित्त, बीमा, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, चिकित्सा और कृत्रिम मेधा जैसी सेवाओं का निर्यात शामिल है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) खोलने में आई तेजी से भी सेवा निर्यात बढ़ रहा है। नैसकाम और जिनोव की ओर से जारी इंडिया जीसीसी-लैडस्केप रपट के मुताबिक, जीसीसी के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। फिलहाल देश में 1800 से अधिक जीसीसी हैं, जिनसे 21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। दुनिया के करीब पचास फीसद जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जीसीसी का योगदान 1.5 फीसद से अधिक है, जो वर्ष 2030 तक 3.5 फीसद हो जाएगा। जीसीसी प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सेवाएं, वित्त, मानव संसाधन और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास तथा नवउद्यम के अनुकूल माहौल से अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने केंद्र यहां खोलना चाहती हैं। वास्तव में भारत के सेवा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता के आगमन से इस क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत जैसे-जैसे रणनीतिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यहां की नई पीढ़ी भी इसमें लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है। ओपन एआइ के प्रमुख सैम आल्ट मैन के मुताबिक, कृत्रिम बुद्धिमता के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं, गुगल के सीईओ सुंदर पिचाई का मानना है कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस समय भारत में कृत्रिम बुद्धिमता पारिस्थितिकी तंत्र का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस वर्ष भारत का कृत्रिम बुद्धिमता का बाजार 13.05 अरब डालर मूल्य की ऊंचाई पर है, जिसका आकार वर्ष 2032 में 130.63 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमता पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान में साठ लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में लगभग 1.8 लाख नवउद्यम हैं और पिछले वर्ष शुरू किए गए नवउद्यमों में से करीब 89 फीसद ने अपने उत्पादों या सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग किया है।

> **इसमें दोराय नहीं कि सेवा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू बन गया है। इससे न केवल विदेशी व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद मिल रही है, बल्कि देश में रोजगार निर्माण में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। नीति आयोग की नई रपट में कहा गया है कि देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 फीसद से अधिक है और लगभग 18.8 करोड़ लोगों को यह रोजगार देता है। सेवा क्षेत्र ने पिछले छह वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए हैं। देश का सेवा निर्यात 14.8 फीसद की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो वस्तु निर्यात के 9.8 फीसद से कहीं ज्यादा है।**

इसमें दोराय नहीं कि सेवा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू बन गया है। इससे न केवल विदेशी व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद मिल रही है, बल्कि देश में रोजगार निर्माण में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। नीति आयोग की नई रपट में कहा गया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 फीसद से अधिक है और लगभग 18.8 करोड़ लोगों को यह रोजगार से जोड़ता है। सेवा क्षेत्र ने पिछले छह वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए हैं। देश का सेवा निर्यात 14.8 फीसद की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो वस्तु निर्यात के 9.8 फीसद से कहीं ज्यादा है।

ऐसे में भारत को सेवा क्षेत्र को और मजबूत करते हुए सेवा निर्यात में तेजी लाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान देना होगा कि अभी भी भू-राजनीतिक रूप से भारत का सेवा क्षेत्र देश की व्यापक आर्थिक असमानता को दर्शाता है। देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु उच्च मूल्य वाली सेवाओं मसलन-सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और अचल संपत्ति में दबदबा रखते हैं। जबकि देश के अधिकांश राज्य अभी भी सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से पीछे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि देश अपने संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अर्थव्यवस्था के औपचारिक एवं शहरीकृत होने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में और भी ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने की क्षमता मौजूद है। सेवा क्षेत्र में लैंगिक समानता पर भी ध्यान देना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 10.5 फीसद महिलाएं सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 60 फीसद है।

यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत के सेवा निर्यात में तेजी लाने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे। साथ ही सेवा निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमें साफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करनी होगी और सेवा निर्यात की संभावनाओं वाले अन्य देशों में कदम बढ़ाने होंगे। हमें नए दौर की तकनीकी जरूरतों और उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को सुसज्जित करना होगा। सेवा निर्यात बढ़ाने के लिए शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ना होगा। देश के कोने-कोने खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को भी सेवा क्षेत्र से जोड़ने के प्रयास करने होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे प्रयासों से देश का सेवा क्षेत्र और सेवा निर्यात रफ्तार पकड़ेगा तथा इससे भारत को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

आपदा का जलवायु

एक तरफ जलवायु परिवर्तन से उपजा संकट लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की गति धीमी पड़ रही है। दुनिया भर में हो रहे नए-नए अध्ययन और वैज्ञानिक शोध चेतावनी देते रहे हैं कि अगर समय रहते इस दिशा में प्रभावी उपाय नहीं किए गए, तो निकट भविष्य में इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन का भारत समेत पूरी दुनिया में प्रभाव साफ दिखने लगा है। ब्राजील के बेलेम में आयोजित काप 30 सम्मेलन में बुधवार को जारी 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' की रपट में कहा गया है कि जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत नौवें स्थान पर है। पिछले तीन दशकों में देश में जलवायु आपदाओं के कारण करीब अस्सी हजार लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की ओर से इस संकट से निपटने को लेकर किए जा रहे दावों के बीच ये आंकड़े वास्तव में चिंताजनक है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकारी प्रयासों को अभी और व्यापक करने तथा उन्हें गति देने की जरूरत है।

रपट के मुताबिक, जलवायु आपदाओं से वर्ष 1995 से 2024 तक लगभग 170 अरब अमेरिकी डालर का आर्थिक नुकसान हुआ है। जान-माल का सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़, चक्रवात, सूखा और तेज गर्मी के कारण हुआ है। इसके पीछे बढ़ता वैश्विक ताप भी एक बड़ा कारक है, जो जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। भारत में यह स्थिति निरंतर खतरे का संकेत दे रही है, क्योंकि बार-बार होने वाली मौसमी आपदाओं से जहां विकास की गति कमजोर होती है, वहीं आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। रपट में कहा गया है कि पिछले वर्ष भारत में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से अस्सी लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हालांकि, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और वन आवरण बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से अमल में लाने की जरूरत है।

अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, तो पिछले तीन दशकों में नौ हजार से अधिक मौसमी आपदाओं ने आठ लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील ली है। यह बात छिपी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर उन्हीं विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है, जिनकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी सबसे कम है। विकासशील देश कमजोर सहन क्षमता और अनुकूलन के सीमित संसाधनों के कारण ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भारत सहित कई विकासशील देशों में जलवायु आपदाएं सामान्य स्थिति बनती जा रही हैं, जिसके लिए तत्काल और व्यापक वित्त पोषित अनुकूलन उपायों की जरूरत है। यह जगजाहिर है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए अनुकूलन उपायों को लेकर उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। उनकी भूमिका सिर्फ वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी और कमजोर देशों के अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करना भी शामिल है।

सरकारी स्कूलों में बनेंगे अत्याधुनिक खेल मैदान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 नवंबर।

राजधानी के सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल के मैदान तैयार किया जाएंगे। इस योजना का मकसद स्कूली बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही विभिन्न खेलों की उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण देना है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक कर विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा विभाग को दिए खाका तैयार करने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस्तृत खाका तैयार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न खेल अकादमियों के साथ साझेदारी करेगी। इसके तहत क्रिकेट, मुक्केबाजी, ताइक्वांडो, फुटबाल, तैराकी और अन्य खेलों के प्रशिक्षण के लिए अकादमियों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन अकादमियों को खेल सुविधाओं के उपयोग की अनुमति और आवश्यक सहयोग भी दिया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही खेलों का व्यवस्थित प्रशिक्षण मिले, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकें।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में 799 स्कूल भवन या परिसर हैं। संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे यह जांच करें कि किन स्कूलों में खेल के मैदान या सभागार विकसित किए जा सकते हैं।

झलकारी बाई कोली की जयंती व पुण्यतिथि मनाएगी सरकार

दिल्ली मंत्रिमंडल ने 'प्रख्यात हस्तियों की जयंती व पुण्यतिथि मनाने की योजना' में वीरांगना झलकारी बाई कोली को शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। पहले से इस योजना में भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, संत गाडगे महाराज और संत दुर्बल नाथ जैसी हस्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झलकारी बाई कोली स्वतंत्रता संग्राम की अदम्य शौर्यगाथा की प्रतीक हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनका योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।

भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना का भारत ने किया अटूट समर्थन

थिंपू, प्रेट्र: भारत ने बुधवार को भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति अपने अडिग समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के साथ वार्ता की और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के तहत आयोजित कालचक्र दीक्षा समारोह में भूटान के नेतृत्व के साथ शामिल हुए।

थिंपू में स्वदेश के लिए रवाना होने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते भूटान नरेश वांगचुक। ● एएनआइ

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-भूटान संबंधों को और प्रगाढ़ करने में सिंग्ये के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि वार्ता ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी में सहयोग पर चर्चा की। नई शहर परियोजना गेलेफू में प्रगति की सराहना की, जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है।' इससे पहले सुबह कालचक्र दीक्षा समारोह का उद्घाटन किया, जिसमें भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और सिंग्ये समेत शीर्ष भूटानी नेतृत्व ने हिस्सा लिया।

नामीबिया के बाद अब बोत्सवाना से आएंगे चीते

गबोरोने, प्रेट्र : भारत में 1952 में विलुप्त घोषित चीतों को फिर से बसाने की परियोजना को रफ्तार मिलने जा रही है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से चीते भारत लाए जाएंगे। भारत और बोत्सवाना ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की राजकीय यात्रा के दौरान आठ चीतों को भारत भेजे जाने की औपचारिक घोषणा की। मुर्मु ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको और वहां की जनता को इस सद्भावना के लिए धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि हम उनकी (चीतों की) अच्छी देखभाल करेंगे।

बोको ने कहा कि उनका देश गुरुवार को प्रतीकात्मक रूप से इन चीतों को महामहिम (मुर्मु) को सौंप देगा। दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आठ चीतों को मोकोलोडी प्राकृतिक अभयारण्य स्थित एक क्वारंटाइन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।

- राष्ट्रपति मुर्मु के बोत्सवाना दौरे पर आठ चीते भेजे जाने का किया गया एलान
- भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए थे चीते, फिर से इन्हें बसाया जा रहा

मुझे यह जानकर विशेष खुशी हो रही है कि बोत्सवाना 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत चीतों को भारत भेजने जा रहा है। 'प्रोजेक्ट चीता' भारत सरकार की एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण पहल है। द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति

गबोरोने में बुधवार को बोत्सवाना के अपने समकक्ष ड्यूमा गिदोन बोको के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। ● एएनआइ

यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना द्वारा भारत को प्रतीकात्मक रूप से चीते सौंपे जाने का साक्ष्य होगा। क्वारंटाइन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन चीतों के कुछ महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है।मुर्मु ने राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि मैं राष्ट्रपति बोको और बोत्सवाना के लोगों की आभारी हूं कि वे अपने चीते भारत भेज रहे हैं। हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। राष्ट्रपति बोको ने कहा-मुझे बताया गया है कि एक चीते का नाम मेरे नाम की तरह ही ड्यूमा रखा गया है। यह नाम गति, चपलता और जरूरत पड़ने पर झपटने की क्षमता का प्रतीक है।

Dainik Jagaran Page No-14

यूनुस भारत से रिश्ते खतरे में डाल कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ा रहे

- हसीना ने कहा, बांग्लादेश के लोग भारत को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं
- अवामी लीग से प्रतिबंध हटे तो अपदस्थ प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाने को तैयार

कोलकाता, प्रेट्र : बांग्लादेश की गैर निर्वाचित मुहम्मद यूनुस सरकार भारत के साथ सहयोग को खतरे में डाल रही है और देश में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। जबकि भारत हमेशा बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यूनुस सरकार की हरकतें मूर्खतापूर्ण और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। ये बातें भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ईमेल के जरिये इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने कहा, अंतरिम सरकार बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, देश के लोग अभी भी भारत को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं।

हसीना ने कहा, उन्होंने ढाका और नई दिल्ली के बीच व्यापक और गहरे संबंध विकसित किए थे। लेकिन यूनुस अपनी मूर्खता से उसमें दरार पैदा कर रहे हैं। हसीना ने मुश्किल वक्त में शरण देने के लिए भारत सरकार का आभार जताया। शेख हसीना ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवामी लीग की भागीदारी उनके बांग्लादेश वापस जाने की मुख्य शर्त होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को उनकी पार्टी अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए।

इंटरव्यू पर जताई चिंता

मुहम्मद यूनुस सरकार पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के आरोपों से तिलमिलाए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में नियुक्त भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बाधे से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इंटरव्यू पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, देश छोड़कर फरार प्रधानमंत्री हसीना को मीडिया से बातचीत की भारत सरकार द्वारा अनुमति देना गंभीर चिंता में डालने वाला है।

एच-1बी वीजा पर ट्रंप का यू-टर्न, कहा हमें दुनिया भर से लानी होंगी प्रतिभाएं

वीजा कार्यक्रम का **बचाव करते** नजर आए, कहा- देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं

न्यूयार्क, प्रेट्र : अपने लगभग हर फैसले पर यू-टर्न लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एच-1बी वीजा पर भी कदम पीछे ले रहे हैं। भारतीय पेशेवरों में लोकप्रिय एच-1बी वीजा पर सख्ती करने वाले ट्रंप का अब इस वीजा कार्यक्रम को लेकर नरम रुख सामने आया है। उन्होंने वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका को दुनिया भर से टैलेंट को लाना होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं।

ट्रंप ने फाक्स न्यूज पर लौरा इंग्राहम को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या एच-1बी वीजा का मुद्दा उनके प्रशासन के लिए बड़ी प्राथमिकता नहीं होगा। अगर कोई अमेरिकी कामगारों का वेतन बढ़ाना चाहता है तो देश में लाखों विदेशी

डोनाल्ड ट्रंप। ● आर्काइव

कामगारों को आने नहीं दिया जा सकता। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, 'मैं सहमत हूं, लेकिन आपको प्रतिभाओं को भी लाना होगा।' जब इंग्राहम ने कहा, 'हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं।' तो ट्रंप ने कहा, 'नहीं, आपके पास नहीं हैं। आपके पास कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं। लोगों को सीखना होगा।' उन्होंने कहा, 'आप लोगों को बेरोजगारी की कतार से हटाकर यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें किसी फैक्टरी में लगा दूंगा, हम मिसाइल बनाएंगे।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'जार्जिया में उन्होंने अवैध प्रवासियों की तलाश में छापे मारे। वहां दक्षिण कोरिया के लोग थे, जिन्होंने जिंदगी भर बैटरी बनाई। आप जानते हैं, बैटरी बनाना बहुत जटिल काम है। यह कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत खतरनाक है। बहुत सारे विस्फोट और बहुत सारी समस्याएं हैं।'

यूएससीआइएस के अनुसार, हालिया वर्षों में जितना एच-1बी वीजा जारी किया है, उसमें 71 प्रतिशत से ज्यादा वीजा भारतीयों को मिला है। 12 प्रतिशत वीजा के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। जबकि 2024 में अमेरिका में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 27 प्रतिशत भारतीय रहे।

ट्रंप ने लड़की के साथ घंटों गुजारे थे...

वाशिंगटन : नामचीन लोगों के जरिये आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करने वाले जेफ्री एप्सटीन के नए ईमेल सामने आने से अमेरिका की राजनीति गरमा गई है। एप्सटीन के किए इन ईमेल में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके घर आए थे और उन्होंने सेक्स ट्रैफिकिंग मामले की पीड़ित लड़की के साथ घंटों बिताए थे। वैसे ट्रंप इन कार्य में शामिल लड़कियों के बारे में जानते थे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने इसे ट्रंप की छवि को खराब करने की डेमोक्रेट नेताओं की साजिश बताया है।

शीघ्र लागू की जाएं चारों श्रम संहिताएं

भारत के कार्यबल को ऐसे औपचारिक रोजगार में तेजी से जगह मिलनी चाहिए, जहां उचित वेतन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिले, जिससे विकास के लाभ से सभी को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो। पुराने श्रम नियमों के बने रहने से गुणवत्तापूर्ण रोजगार देने की उद्यमों की क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित हुई। इसी के आलोक में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम सुधारों की जो कल्पना की, वह काफी समय से लंबित थी। इन्हें 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा चार श्रम संहिताओं के रूप में पारित किया गया। ये संहिताएं देश के श्रम परिदृश्य को आधुनिक बनाने और संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं। दशकों पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाते हुए चार नई श्रम संहिताओं के निर्माण का उद्देश्य न केवल कानूनों को एकीकृत स्वरूप प्रदान करना है, बल्कि काम को अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित और उत्पादक बनाना है।

मजदूरी संहिता, 2019 यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है कि प्रत्येक श्रमिक को श्रम की गरिमा का सम्मान करने वाला न्यूनतम वेतन मिले। पहले न्यूनतम वेतन केवल निर्धारित व्यवसायों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे सभी क्षेत्रों और संगठित और असंगठित के समस्त श्रमिकों पर लागू कर दिया गया है। यह न्यूनतम वेतन का सार्वभौमीकरण श्रमिकों को कानूनी रूप से बुनियादी वेतन का अधिकार देता है। इसके साथ ही पहली बार एक राष्ट्रीय आधार वेतन (फ्लोर वेज) की व्यवस्था की गई है, जिसे केंद्र सरकार जीवन स्तर और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय करेगी। कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं तय कर सकेगा। इससे राज्यों के बीच वेतन असमानता भी घटेगी और देशभर के श्रमिकों को समान अवसर मिलेगा। संहिता यह भी सुनिश्चित करती है कि वेतन की समीक्षा नियमित रूप से हो, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप श्रमिकों की आय प्रासंगिक बनी रहे। इस संहिता के तहत विवादों में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार नियोक्ता पर होगा, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी।

हिरण्मय पंड्या

जब पारंपरिक नौकरियां घट रही हैं, तब श्रम संहिताएं संतुलित विकास का ढांचा प्रदान करने में सक्षम होंगी

समय की मांग है श्रम सुधार ● फाइल

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 स्वतंत्र भारत में जन कल्याण के सबसे समावेशी विस्तारों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम सहित नौ प्रमुख कानूनों को मिला कर यह एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करती है, जो पारंपरिक और नए, दोनों प्रकार के कार्यों को कवर करती है। पहली बार गिग श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय कार्यबल का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक श्रमिक को पंजीकृत किया जाएगा, उसे एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व सहायता जैसे लाभ का सीधा वितरण संभव हो सकेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 राष्ट्र का निर्माण करने वालों के प्रति देखभाल और जिम्मेदारी का एक संदेश है। प्रतिष्ठान की परिभाषा को व्यापक बनाकर यह संहिता उन लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो पहले सुरक्षा कानूनों के दायरे में नहीं आते थे। प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी का विवरण, पदनाम, श्रेणी, वेतन का ब्यौरा तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विवरण सम्मिलित होंगे। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करती है और नियोक्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे इस मद में कर्मचारियों पर कोई वित्तीय बोझ न डालें और सुरक्षित एवं स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें। यह संहिता लैंगिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति करती है। यह महिला श्रमिकों को सभी प्रतिष्ठानों और रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देती है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तीन पुराने अधिनियमों को एकीकृत ढांचे में मिला करके नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों में स्पष्टता लाती है। इसमें बीस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को शिकायत निवारण समितियां गठित करने का प्रविधान है, ताकि विवादों का शीघ्रता से समाधान हो जाए तथा हड़ताल या मुकदमेबाजी की स्थिति न बने। इस संहिता के तहत छंटनी का सामना कर रहे श्रमिक अब 30 दिन का नोटिस और पर्याप्त मुआवजा पाने के हकदार हैं। यह एक मानवीय सुधार है, जो आजीविका सुरक्षा का सम्मान करता है।

विभिन्न विकासशील देशों के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि श्रम सुधारों ने उनकी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थिति, बढ़ते टैरिफ तथा व्यापार ढांचों में बदलाव को देखते हुए भारत में नई श्रम संहिताओं को जल्द से जल्द लागू करना अत्यंत आवश्यक है। श्रम नियम सरल एवं पारदर्शी होने पर निवेश बढ़ेगा, औपचारिक रोजगार बढ़ेगा तथा श्रमिकों के गरिमापूर्ण अधिकार सुनिश्चित होंगे।

स्वचालन और डिजिटलीकरण के युग में जब पारंपरिक नौकरियां घट रही हैं, तब ये संहिताएं संतुलित विकास का ढांचा प्रदान करने में सक्षम होंगी। चारों श्रम संहिताएं उस महत्वाकांक्षा की रीढ़ हैं, जिसमें आर्थिक गतिशीलता को सामाजिक न्याय के साथ जोड़कर एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की कल्पना की गई है।

(लेखक भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

सबको लड़नी होगी आतंक के खिलाफ लड़ाई

अवधेश कुमार

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों का काम तब आसान होगा, जब देश के आम नागरिक भी सचेत रहेंगे

जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष देश पिछले लगभग एक दशक से आतंकी हमलों से करीब-करीब मुक्त था, लेकिन दिल्ली में लाल किले के निकट कार में हुए विस्फोट ने फिर से पुराने दौर की याद दिला दी, जब कुछ अंतराल पर एकल या शृंखलाबद्ध धमाकों से देश दहल जाता था। शेष देश में लंबे समय तक कोई बड़ी आतंकी घटना न घटने से आम लोग निश्चिंत थे कि अब आतंकी हमले नहीं कर सकेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, हरियाणा के फरीदाबाद, गुजरात और दिल्ली तक बरामद विनाशकारी सामग्री तथा गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों के कारण उनकी चिंता फिर बढ़ गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से देश के कई हिस्सों से किसी न किसी आतंकी माड्यूल के पकड़े जाने की खबर आ रही है। पिछले दिनों ही गुजरात में हैदराबाद के एक डाक्टर को घातक रसायन बनाने की सामग्री और हथियारों के साथ पकड़ा गया। उसके दो साथी भी गिरफ्तार किए गए, जो उत्तर प्रदेश के हैं।

इस साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जब धर्म पूछ कर 26 लोगों की हत्या की थी तो भारत ने इसके जवाब में आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूहों के मुख्य अड्डों को ध्वस्त कर सीमा पार आतंकवाद पर अब तक का सबसे बड़ा आघात किया था। निश्चय ही उसी के बाद से वे बड़े प्रतिशोध का षड्यंत्र रच रहे होंगे। लाल किला विस्फोट के तरीके और अब तक सामने आए षड्यंत्र की कहानी में छह वर्ष पहले पुलवामा हमले की जिहादी आतंक की कड़ी दिखती है। यद्यपि छानबीन के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, बावजूद इसके पीछे की घटनाएं एक-दूसरे से जुड़ी लगती हैं।

श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगने के बाद पुलिस ने आतंकवादियों के कुछ हमदर्द और पत्थरबाज गिरफ्तार किए। उनसे एक मौलवी का पता चला, जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। उससे पूछताछ के बाद अनंतनाग के रहने वाले डा. आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब उसे लेकर श्रीनगर पहुंची और पूछताछ की तो अनंतनाग के सरकारी अस्पताल से उसके ठिकाने से असाल्ट राइफल मिली। पुलिस ने और पूछताछ की तो पुलवामा जिले के डा. मुजम्मिल का पता चला। इससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जब फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह मेडिकल कालेज

अवधेश राजपूत

में कार्रवाई की तो उसे 360 किलोग्राम विस्फोटक, एक एके-47 राइफल और 84 कारतूस सहित टाइमर, जिलेटिन के छड़ और अन्य सामग्रियां मिलीं। उसके बाद जांच की कड़ियां पुलिस को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव तक ले गईं, जहां एक घर में विस्फोटक के ढेर देखकर उसके होश उड़ गए। धौज से फतेहपुर तगा गांव चार किलोमीटर दूर है। डा. मुजम्मिल ने मौलाना इश्तियाक से यह घर किराए पर ले रखा था। करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद होना सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है।

अभी तक इस प्रकरण में गिरफ्तार लोग उच्च शिक्षा प्राप्त और संपन्न परिवार के हैं। डा. मुजम्मिल फिजिशियन है और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कालेज में पढ़ाता था और गिरफ्तार किए गए शोपियां के मौलवी इरफान अहमद, श्रीनगर के मकसूद अहमद डार, आरिफ निसार डार और यासिर उल अशरफ, गांदरबल के जमीर अहमद अहंगर में से कोई निर्धन, बेरोजगार या अनपढ़ नहीं है। लाल किला विस्फोट में मारा गया डा. उमर नबी एमडी मेडिसिन डिग्री के साथ फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कालेज में डाक्टर था। डा. आदिल उसका साथी है। इनकी एक साथी डा. शाहीन लखनऊ की है। उसकी कार से एक राइफल मिली थी। फरीदाबाद माड्यूल में कुछ और डाक्टर शामिल पाए जा सकते हैं। जांच से ही पता चलेगा कि इन्होंने क्यों आतंकवादी माड्यूल बनाया? किस तरह इतना विस्फोटक, हथियार इकट्ठे किए, कौन-कौन इसके पीछे थे और कहां-कहां विस्फोट करने की साजिश थी?

पिछले तीन दशकों की जिहादी घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि आतंकियों को लाल किला विस्फोट की प्रेरणा अपने कट्टर मजहबी सोच से मिली। इसी कारण यह जानते हुए कि विस्फोट में वे स्वयं भी मारे जाएंगे या पकड़े गए तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा, उन्होंने सब कुछ किया। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों से हम कुछ समय के लिए उन्हें कमजोर कर सकते हैं, पर दुनिया का इस्लामीकरण करने, काफिरों को सबक सिखाने के घातक मजहबी सोच को समाप्त करना आसान काम नहीं है। फरीदाबाद में एक व्यक्ति किराए पर घर लेकर भारी मात्रा में विस्फोटक लाता रहा, लेकिन मकान मालिक या किसी अन्य ने उसे रोकने-टोकने या पुलिस को खबर करने की कोशिश नहीं की। संभव है इन आतंकियों को स्थानीय लोगों का सहयोग मिला हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत सहित विश्व में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ज्यादातर में स्थानीय लोगों का सहयोग रहा है। जब पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और मदीना के बाद कलमे की बुनियाद पर बनने वाली दूसरी रियासत पाकिस्तान है तथा कश्मीर हमारे गले की नस है तो यह समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कितना कठिन है। पाकिस्तान को अमेरिका और तुर्किये जैसे देशों का मिलता सहयोग आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन साबित हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक-एक व्यक्ति के साथ भारत के सभी नागरिकों को हर क्षण जागरूक और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। पता नहीं कौन हमारे आसपास जिहादी मानसिकता से लैस होकर भयानक हिंसा का षड्यंत्र रच रहा हो। एक राष्ट्र के नाते भारत का संकल्प आतंकवाद का समूल नाश करना है। इस संकल्प को बल तब मिलेगा, जब हर नागरिक आतंक के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सजगता का परिचय देगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

मतदान में आगे महिलाएं

बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जिस तरह आगे बढ़कर मतदान किया है, वह हमारे लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है। पुरुष मतदाताओं में से 62.8 ने मतदान किया, जबकि महिलाओं में 71.6 प्रतिशत ने मतदान से सबको चकित कर दिया। महिलाओं की बढ़ी भागीदारी की बदौलत ही बिहार में इस बार कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। एक समय था, जब आधी महिलाएं भी मतदान के लिए आगे नहीं आती थीं। साल 1962 की बात करें, तो 32.47 प्रतिशत महिलाओं ने ही मतदान किया था, इसका परिणाम यह था कि तब बिहार में कुल मतदान 45 प्रतिशत भी नहीं होता था। पहले दस में से तीन महिलाएं ही मतदान करती थीं, जबकि अब सात से ज्यादा महिलाएं मतदान करने लगी हैं। यह अध्ययन का विषय है कि बिहार राज्य में यह सकारात्मक परिवर्तन कैसे हुआ? वैसे, यह बदलाव बिहार में पहले ही हो जाना चाहिए था। यहां तक पहुंचने में छह दशक से ज्यादा समय लग गया।

यहां यह अवश्य रेखांकित करना चाहिए कि वास्तविक या निष्पक्ष मतदान के दौर में अगर देखें, तो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था, उसमें दस में से पांच महिलाएं भी मतदान के लिए नहीं निकलती थीं। साल 2005 के चुनाव में 44.49 प्रतिशत महिलाओं ने ही मतदान किया था। इसके अगले दस वर्ष में महिलाओं को जमीनी मजबूती मिली, तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान का प्रतिशत बढ़कर 60.48 हो गया। पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ, तब कोरोना महामारी का असर था, तो मतदान में मामूली गिरावट दर्ज हुई थी। बेशक, अब 2025 में हुए रिकॉर्ड मतदान से महिलाओं के मनोबल को बहुत मजबूती मिलेगी। साल 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू हुई थी, जिसने बड़ी संख्या में लड़कियों को स्कूल पहुंचाया। निस्संदेह, स्कूल जाने वाली पीढ़ी आज आगे बढ़कर मतदान कर रही है। अगर स्कूल जाने की बाधाएं कम हुई हैं, तो मतदान की बाधाओं का भी अंत हुआ है। एक दौर वह भी था, जब परिवार के पुरुष सदस्य महिलाओं को मतदान से रोकते थे। अब महिलाओं की ऐसी पीढ़ी आई है, जो पुरुष सदस्यों के रोके नहीं रुकने वाली। पहले पुरुष ही तय करते थे कि किसे वोट देना है, लेकिन अब बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं अपना उम्मीदवार चुनने लगी हैं। भय और बाधा का दूर होना लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है।

बिहार में पहले दस में से तीन महिलाएं ही मतदान करती थीं, जबकि अब सात से ज्यादा महिलाएं मतदान करने लगी हैं। बेशक, बिहार ने एक लंबा सफर तय किया है।

यहां यह भी रेखांकित करना चाहिए कि साल 2006 में बिहार में महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इससे गांव-गांव में उनकी ताकत बढ़ी। अब बिहार की पंचायतों में 58 प्रतिशत मुखिया व उप-मुखिया महिलाएं हैं। वहां से लेकर जीविका दीदी तक, बिहार में महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि बिहार में महिला साक्षरता भी इस सदी में दोगुनी हुई है। फिर भी खासकर ग्रामीण इलाकों में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच करीब 20 प्रतिशत का अंतर है। निश्चित रूप से गांवों में मतदान के मामले में महिला-पुरुष के बीच इतना अंतर नहीं होगा। स्नातक स्तर पर तुलना करें, तो बिहार में जहां 18 लाख से ज्यादा पुरुष स्नातक हैं, वहीं चार लाख के करीब महिलाएं स्नातक हैं। लगभग ऐसा ही बड़ा अंतर रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में है। अतः बिहार की जो महिलाएं मतदान के मामले में पुरुषों से आगे निकली हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर भी तेजी से आगे आना चाहिए।

जहरीले प्रदूषण से दिल्ली का जीतना देश के लिए जरूरी

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली | पर्यावरणविद्

यहां स्कैन करें

राजधानी दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। पिछले करीब एक महीने से यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही और अब तो नागरिक भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। आलम यह है कि राज्य सरकार को दिल्ली में 'ग्रैप-3' की पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। निर्माण कार्यों, डीजल वाहनों और खनन कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पांचवीं तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं लेने और लोगों से निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल की अपील की गई है। दिल्ली के प्रदूषण का असर देश भर की मनःस्थिति पर पड़ता है कि आखिर राजधानी ही जब इस समस्या का निदान नहीं कर पा रही, तो फिर छोटे शहरों के वैश्विक प्रदूषण का क्या होगा?

वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है और यह मानव स्वास्थ्य के साथ इस ग्रह की सेहत व जलवायु परिवर्तन पर भी असर डालता है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि स्वच्छ हवा हरेक जगह सभी सामाजिक-आर्थिक वर्ग के लोगों को उपलब्ध होनी ही चाहिए। 7 सितंबर, 2021 को आयोजित 'इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एअर फॉर ब्लू स्काई' का विषय था- स्वस्थ हवा, स्वस्थ ग्रह। इस दिवस का उपयोग वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के अंतरसंबंधों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। इसके बाद ही भारत में 16 दिसंबर, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वाधिक वायु प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को यह दायित्व सौंपा था कि वह जन-सामान्य व विशेषज्ञों की राय से दिल्ली प्रदूषण का कोई स्थायी समाधान निकाले।

> **पूरे देश में यह पैगाम जाता है कि जब राजधानी तमाम उपायों के बाद इस समस्या का निदान नहीं कर पा रही, तो छोटे शहर भला क्या करें?**

इस आदेश के बाद धुएं से बचाव की निगरानी के लिए लगभग 250 टीमें, निर्माण स्थलों पर नजर रखने को 75 और वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच में 500 टीमें लगाई गईं। भवन-निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक लगी। जारी निर्माण कार्यों के लिए चेक लिस्ट व संहिता बनीं। ग्रीन मार्शल नियुक्त किए गए। नियमों का पालन न करने वाली निर्माण इकाइयों पर भारी जुर्माना लगता था। दिल्ली की शीतकालीन योजना में अनावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रोक दिया गया था। दस साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराने डीजल वाहनों को स्क्रैप करने व 65 चिह्नित जाम वाली सड़कों पर जाम न होने देने की योजना बनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने ही दिल्ली में स्मॉग टॉवर लगाने का सुझाव दिया था। फिर भी, दिल्ली प्रदूषण का अस्थायी समाधान तक नहीं निकला। यह चिंता का विषय होना चाहिए

दिल्ली को स्थायी समाधान चाहिए, तो पिछली शीतकालीन योजना की सीमाओं को परखते हुए उससे सीख लेनी चाहिए। प्रदूषण रोकथाम की योजना चाहे कितने ही विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित हो, बाहर से आ रहे प्रदूषण पर रोक लगाए बिना वह सफल नहीं हो सकती है।

स्थायी समाधान के लिए प्रदूषण के मूल स्रोतों पर नियंत्रण करना होगा। पटाखे और कूड़ा जलाने पर पूर्ण रोक इस दिशा में कारगर हो सकती है। कूड़े के पहाड़ों को हर हाल में हटाना ही होगा। करीब 25-26 प्रतिशत वायु प्रदूषण घरों के ठोस ईंधन से निकला हुआ होता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। सल्फर डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया जैसे जाने हुए प्रदूषकों के अलावा ठोस पीएम 2.5 प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी तय सीमा में बांधना ही होगा। इसके साथ ही उन पर्यावरण नियमों, नीतियों व मानकों को लागू किया जाए, जिससे हवा में पहुंचने वाले प्रदूषणों का कम से कम उत्सर्जन हो। एक्सप्रेस-वे की दोनों तरफ पौधे लगें, तो वे प्रदूषण-शोषक का काम करेंगे। कोयला आधारित बिजली उत्पादन वाली इकाइयों और डीजल से चलने वाले जेनरेटरों का विकल्प ढूंढ़ना होगा। वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए भ्रष्टाचार और कुशासन से लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके कारण सभी उपाय सही से जमीन पर लागू नहीं हो पा रहे।

अमेरिका ने सन् 1970 में ही साफ हवा के मानक व कानून घोषित कर दिए थे, किंतु अभी भी कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता का स्तर इनसे काफी नीचे चला जाता है। अतः हताशा छोड़कर वायु प्रदूषण को कम से कम करने की राह पर हमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत-अमेरिका रिश्ते में नई उम्मीदें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन

दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप का एच-1बी वीजा पर नया रुख सुधरते संबंधों की तस्दीक करता है।

अपने आक्रामक रुख से कूटनीतिक संबंध तक को दांव पर लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब संभवतः नरम पड़ने लगे हैं। एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर उनका ताजा बयान कम-से-कम यही संकेत दे रहा है। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका को प्रतिभाओं की जरूरत है, इसलिए 'खास भूमिकाओं' के लिए उनको बुलाया जाएगा। जाहिर है, यह भारतीय पेशेवरों के लिए एक राहत भरी खबर है, जिनकी पेशानी पर तब बल पड़ गए थे, जब ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि का एलान किया गया था। जबकि, इन्हीं भारतीयों की योग्यता पर अमेरिकी टेक कंपनियां निर्भर रही हैं।

हालांकि, इससे पहले भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी सहमति जताई है। वास्तव में, दोनों देशों के रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ रक्षा साझेदारी है, जो पिछले दो दशकों की हथियारों की खरीद, तकनीक के हस्तांतरण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तालमेल से पुष्ट होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विपक्षीय संबंधों में अपेक्षा व वास्तविकता के बीच का अंतर खत्म होने लगा है, जिसकी वजह निस्संदेह राजनीतिक व सुरक्षा संबंधों का लगातार सुधरना है।

बेशक, राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक के बाद दूसरी प्रतिकूल राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, जिनसे धारणा और तरक्की के बीच की खाई घटने के बजाय बढ़ गई है। खासतौर से ट्रंप के नाटकीय रुख से यही सोच बनी कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। फिर भी, उम्मीद जगाने वाली कवायदें निरंतर चलती रही हैं। रक्षा समझौते के बाद ट्रंप का एच-1बी वीजा पर यह नया रुख इसी की तस्दीक करता है।

नए 'डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' को कम से कम चार कारणों से बेहद अहम माना जा रहा है। पहला, यह समझौता राजनीतिक रूप से ऐसे संवेदनशील समय में हुआ है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लाद रखा है। दूसरा, दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापार का रिश्ता चोली-दामन सा रहा है, लिहाजा रक्षा समझौता आश्वस्त करता है कि व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत भी देर-सबेर पटरी पर आ जाएगी। तीसरा, इस समझौते के बाद न सिर्फ भारत को महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की तेज आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि तकनीकी सहयोग व उसके हस्तांतरण की राह भी आसान हो सकती है।

चौथी व आखिरी वजह। यह समझौता द्विपक्षीय सहयोग के दशकों पुराने उस वायदे को आगे बढ़ाता है, जो 1995 में अमेरिका व भारत के बीच रक्षा संबंधों को लेकर 'एग्रीड मिनट' (सहमत कार्यवृत्त) पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ शुरू हुआ था। यह शीत युद्ध के बाद के दौर में दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक रक्षा समझौता था। साल 2005 में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने एक नया समझौता करके इसको आगे बढ़ाया था। इसके बाद, जून 2015 में भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐश कार्टर ने भी एक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।

नया डिफेंस फ्रेमवर्क भारत और अमेरिका के रक्षा व सुरक्षा संबंधों को नई दिशा देने का काम करेगा। वह भी ऐसे वक्त में, जब तकनीक ही नहीं, युद्ध का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है, और युद्ध-क्षेत्र की जरूरतें, प्रौद्योगिकियां और प्रकृति में तेज बदलाव नजर आ रहे हैं। इस फ्रेमवर्क से द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी में एक मजबूत भरोसा बनेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय-समय पर समीक्षा और उसी के अनुसार सुधार की प्रक्रिया भी हो सकेगी।

इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता, प्रतिरोध, तकनीकी सहयोग और सूचनाओं के लेन-देने के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में इससे फायदा तो मिल ही रहा है, इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व स्थिरता को लेकर दीर्घकालिक सामरिक नजरिये की झलक भी मिलती है। इसमें मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया गया है, जो ट्रंप के इस दूसरे शासनकाल के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा में घटते भरोसे को फिर से मजबूत बनाने का काम कर सकता है। हालांकि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ट्रंप प्रशासन की बदलती सामरिक नीतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी सोच के बीच अंतर करना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम जान सकेंगे कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वह कभी-कभी अप्रतिबद्ध रवैया क्यों अपनाता है?

वास्तव में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की घोषित प्रतिबद्धता में अंतर तब दिखता है, जब चीन के साथ आर्थिक समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह बेकरार नजर आता है। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ही अमेरिका और चीन ने एक आर्थिक समझौते पर सहमति जताई है, जो अमेरिकी कंपनियों को राहत पहुंचा सकती है और उनकी आपूर्ति श्रृंखला में मदद कर सकती है। मगर इसने 'क्वाड' के तहत भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय साझेदारों के साथ बनाए गए तालमेल को खतरे में भी डाल दिया है। इससे मुमकिन है कि इस क्षेत्र में अमेरिका को कुछ रणनीतिक नुकसान हो। इसी तरह, नए रक्षा ढांचे को भी क्रियान्वयन के दौरान कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है।

साल 2015 के फ्रेमवर्क का यदि कोई सबक है, तो यही कि भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को लेकर फैसले लेने और तालमेल बनाने में तेजी लानी चाहिए। पिछले दशक की प्रतिबद्धताएं अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं, विशेष रूप से रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त नवाचार को प्रोत्साहित करने और साझा तकनीकी व औद्योगिक संबंध विकसित करने के मामले में। इतना ही नहीं, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान निवेश बढ़ाने के लिए दिए जा रहे राजनीतिक व कूटनीतिक दबावों को देखते हुए एक खतरा यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्ता 'क्रेता-विक्रेता मॉडल' में न ढल जाए। यह एक ऐसा मॉडल है, जिससे ऊपर उठने का फैसला दोनों देशों ने 2015 में ही कर लिया था।

लिहाजा, अब दोनों देशों को इस नए दशकीय सुरक्षा समझौते को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंध अब भी साझा नवाचार, आपसी विश्वास और रणनीतिक नजदीकी पर टिके रहें। शर्तों के मुताबिक, साल 2035 में इस समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा। मगर दस वर्षों का यह रास्ता काफी लंबा है और दोनों देश इसे कैसे तय करते हैं, इसी से द्विपक्षीय रक्षा व सुरक्षा संबंधों का अगला अध्याय लिखा जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page No-10

केर स्टार्मर | ब्रिटिश प्रधानमंत्री

हर बच्चे को ऐसा जुनून विकसित करने का मौका मिलना चाहिए, जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए और एक सफल करियर के लिए जरूरी कौशल सिखाए। इसके लिए गणित, अंग्रेजी के साथ रचनात्मक विषयों की अहमियत भी पहचाननी होगी।

Hindustan Page No-10